रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112022-240672
CG-DL-E-30112022-240672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5324] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944
No. 5324] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5556(अ).— केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सोमालिया और इरीट्रिया से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों को लागू करने के बाबत आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सोमालिया और इरीट्रिया से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प को लागू करने के बाबत (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2022 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. सोमालिया और इरीट्रिया से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों को लागू करने के बाबत आदेश, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) का प्रस्तावना में, "और 2244 (2015)" अंको, कोष्ठकों और शब्द के स्थान पर "2244 (2015), 2607 (2021) और 2628 (2022)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

3. उक्त आदेश के पैरा 2 के, उप-पैरा (1) के, खंड (क) में "और 2244 (2015)" अंक, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "2244 (2015), 2607 (2021) और 2628 (2022)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश के पैरा 4 के शीर्ष "I. आयुध पर रोक" के खंड (ग) के, परंतुक में, -

(क) मद (ii) में, कोष्ठक, शब्द और अंक "संकल्प सं. 2111 (2013) के अनुबंध में हो {संकल्प सं. 2111 (2013) के पैरा 10 (क) के सन्दर्भ में}" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात:-

"संकल्प सं. 2111 (2013) और संकल्प 2607 (2021) के अनुबंध क और अनुबंध ख में हो [संदर्भ संकल्प 2607 (2021) का पैरा 24-25]"।

(ख) मद (iii) में उप-मद (घ) के पश्चात, निम्नलिखित उप मदें अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:

"(ङ) सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (एएमआईएसओएम) को सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन (एटीएमआईएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा [संकल्प 2628 (2022) के पैरा 22 और 25];

(च) एफजीएस (एसएसएसआई) के अलावा सोमालिया के सुरक्षा क्षेत्र संबंधी संस्थान;"

(ग) मद (vii) के पश्चात, निम्नलिखित मदें अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"(viii) रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों को ले जाने वाले जहाजों की अस्थायी यात्राओं के लिए सोमालिया के बंदरगाहों में प्रवेश, परन्तु ऐसी मदें हर समय ऐसे जहाजों पर ही रहें [संकल्प 2607 का पैरा 34 (घ)];

(ix) हथियारों और सैन्य उपकरणों की डिलीवरी, या तकनीकी सलाह, वित्तीय और अन्य सहायता, और सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण का प्रावधान, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से निम्नलिखित का विकास हो:

(i) एफजीए का सोमाली राष्ट्रीय सुरक्षा बल(एसएनएसएफ), सोमाली लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संकल्प 2607 के अनुबंध क और ख में शामिल मदों से संबंधित मामलों को छोड़कर, जो मामला-दर-मामला आधार पर समिति के पूर्व अनुमोदन तथा समिति की सूचनार्थ क्रमशः संकल्प 2607 के पैरा 21 (क), 23 और 24 में अग्रिम अधिसूचना के अध्यधीन हैं];

(ii) एफजीएस (एसएसएसआई) से संबंधित संस्थाओं के अलावा सोमाली सुरक्षा क्षेत्र संबंधी संस्थान, सोमाली लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संकल्प 2607 के अनुबंध क और ख से संबंधित मदों को छोड़कर, जो लागू अनुमोदनों तथा अधिसूचना संबंधी प्रक्रियाओं के अध्यधीन हैं [जैसा कि संकल्प 2607 के पैरा 21 (ख) और (ग), 25 और 26 में निर्धारित किया गया है]।

5. उक्त आदेश के उपाबंध 5 के पश्चात, निम्नलिखित उपाबंध सम्मिलित किए जाएंगे अर्थात -

उपाबंध 6

संकल्प 2607 (2021)

सुरक्षा परिषद द्वारा 15 नवंबर 2021 को हुई इसकी 8905 बैठक में अंगीकृत किया गया

सुरक्षा परिषद,

अपने पिछले सभी प्रस्तावों और सोमालिया की स्थिति के संबंध में इसके राष्ट्रपति के वक्तव्य को *स्मरण करते हुए*,

सोमालिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एकता के लिए अपने सम्मान की *पुष्टि करते हुए,* तथा क्षेत्रीय विवादों के अस्थिर करने वाले प्रभावों को सोमालिया में फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई के महत्व को *रेखांकित करते हुए,*

सोमालिया की संघीय सरकार (एफजीएस) तथा सोमालिया के संघीय सदस्य राज्यों (एफएमएस) के बीच 17 सितंबर 2020 और 27 मई 2021 को हुए करारों का *स्वागत करते हुए,* एफजीएस और एफएमएस से इन करारों को लागू करने तथा 2021 में शांतिपूर्ण, विश्वसनीय और समावेशी चुनाव संपन्न कराने का *आग्रह करते हुए,*

यह विश्वास करते हुए कि सोमालिया में राज्य-निर्माण की सतत प्रगति अल-शबाब सहित आतंकवादी समूहों को सोमालिया की स्थिति का अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकेगी, सोमालिया की संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगातार हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं संबंधी प्रगति के महत्व को रेखांकित करते हुए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना, सोमालिया संक्रमण योजना (2021) (एसटीपी), नौवीं राष्ट्रीय विकास योजना और संयुक्त रूप से सम्मत पारस्परिक जवाबदेही संरचना, तथा एक संघीय पुलिस एवं न्याय प्रणाली, वित्तीय संघवाद, शक्ति और संसाधन की साझेदारी, तथा संवैधानिक समीक्षा पर समझौता करना शामिल हैं, इस संबंध में 27 मई 2021 को सम्मत रोडमैप का स्वागत करते हुए, और एफजीएस और एफएमएस से इसे बिना विलंब लागू करने का आग्रह करते हुए,

अपने राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को विकसित करने में इसकी आवश्यकताओं के मद्देनज़र अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहभागियों के साथ समन्वय करने के लिए एफजीएस को प्रोत्साहित करते हुए, यह संज्ञान में लेते हुए कि इन बलों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए इस संकल्प में दिए गए उपायों के अनुसार हथियारों और विशेष उपकरणों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है,

राष्ट्रीय डब्ल्यूएएम रणनीति को अपनाने सहित हथियार एवं गोला-बारूद प्रबंधन (डब्ल्यूएएम) पर एफजीएस द्वारा की गई प्रगति का स्वागत करते हुए, हथियार एवं गोला-बारूद प्रबंधन संबंधी नीतियों को संहिताबद्ध और कार्यान्वित करने के लिए सतत कार्य, जिसमें सोमालिया के समस्त सुरक्षा बल के लिए एक जवाबदेह हथियार वितरण और अनुरेखण प्रणाली का विकास करना शामिल है, हेतु अनुरोध करते हुए, यह स्वीकार करते हुए कि प्रभावी हथियार एवं गोला-बारूद प्रबंधन एफजीएस और एफएमएस का दायित्व है, तथा एफजीएस और एफएमएस को इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए सोमालिया के सहभागियों को प्रोत्साहित करते हुए, और सोमालिया की राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना और एसटीपी का अनुसरण करते हुए,

शस्त्र प्रतिरोध का उल्लंघन करते हुए सोमालिया को और उसके जरिए हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति की निंदा करते हुए, विशेषत: जब वे अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े सहयोगियों तक पहुंचते हैं, और जब वे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में सोमालिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमज़ोर करते हैं, तथा यमन से सोमालिया तक हथियारों, गोला-बारूद और आईईडी घटकों की निरंतर अवैध आपूर्ति की भी निंदा करते हुए ,

सोमालिया और उसके बाहर अल-शबाब के आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए, इस विषय में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि अल-शबाब विशेष रूप से तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) का उपयोग बढ़ाकर और वैध वित्तीय प्रणाली का अनुचित लाभ लेने के माध्यम से सोमालिया और इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, तथा सोमालिया में 'इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड दि लेवांट' (आईएसआईएल जिसे दा' एश के नाम से भी जाना जाता है) से जुड़े सहयोगियों की निरंतर उपस्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए,

उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून, और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सहित संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय कानून संबंधी चार्टर के अनुसार, आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरों को हर संभव तरीके से रोकने की आवश्यकता की पुष्टि करते हुए,

यह स्वीकार करते हुए कि अल-शबाब द्वारा सोमालिया और इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए जो खतरा उत्पन्न किया गया है वह इस संगठन की पारंपरिक सैन्य कार्रवाई और अनियमित युद्ध प्रणाली से अधिक खतरनाक है, अल-शबाब की राजस्व उत्पादन की क्षमता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जैसाकि सोमालिया (एस/2021/849) पर

विशेषज्ञों के पैनल (दि पैनल) की अंतिम रिपोर्ट में दर्ज है, सोमालिया के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एफजीएस के प्रयासों का स्वागत करते हुए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों की पहचान और निगरानी की जा सके तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोका जा सके, संस्थागत क्षमता निर्माण पर एसटीपी में एफजीएस द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों को संज्ञान में लेते हुए जो सोमालिया के आर्थिक भविष्य को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करते हैं, अल-शबाब के वित्त-पोषण को बाधित करने के उद्देश्य से एक योजना विकसित करने के लिए एफजीएस, ड्रग्स एंड क्राइम संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) और दि पैनल द्वारा किए गए प्रयासों का भी स्वागत करते हुए, तथा इस प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करने के लिए एफजीएस, एफएमएस, सोमालिया के वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहभागिता का अनुरोध करते हुए,

सोमालिया में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों के विपथन की लगातार खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एफजीएस द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत करते हुए जिसमें 21 सितंबर 2019 को भ्रष्टाचार-रोधी कानून का प्रवर्तन और भ्रष्टाचार-रोधी आयोग की स्थापना, तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन शामिल है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र के सकारात्मक कार्य को सुदृढ़ करने में एफजीएस और एफएमएस द्वारा की गई प्रगति का स्वागत करते हुए, और भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयास जारी रखने, और सुधार की गति में तेजी लाना जारी रखने के लिए एफजीएस और एफएमएस का आह्वान करते हुए,

चारकोल के निर्यात को कम करने के लिए एफजीएस,एफएमएस और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा चारकोल गंतव्य बाज़ारों के साथ किए गए उपायों का स्वागत करते हुए, निर्यात बिंदुओं पर मौजूदा चारकोल भंडार की निगरानी और नियंत्रण के लिए अनुरोध करते हुए, चारकोल पर सोमालिया की राष्ट्रीय नीति, जिसका उद्देश्य चारकोल-भंडार के निपटान हेतु अंतर्देशीय चारकोल उपयोग के स्थायी प्रबंधन का विकास करना है, के विकास को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए,

चीनी के व्यापार का अनुचित लाभ उठाने की अल-शबाब की कथित क्षमता पर चिंता *व्यक्त करते हुए* तथा एफजीएस, एफएमएस और क्षेत्रीय हितधारकों से इसके समाधान हेतु आग्रह करते हुए,

सोमालिया के क्षेत्राधिकार वाले समुद्री क्षेत्र में अवैध और अनियमित मछली पकड़ने की निरंतर रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त करते हुए, अवैध रूप से मछली पकड़ने और अल-शबाब की राजस्व उत्पादन की क्षमता के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोमालिया के उपयुक्त कानून के अनुसार मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से सोमालिया के अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए, समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता और प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार करने के लिए एफजीएस, एफएमएस और सोमालिया के अधिकारियों को यूएनओडीसी, उनके अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करते हुए,

गलमुदुग की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, 2021 के चुनावों से पहले और उसके बाद विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को दोहराते हुए, तथा सोमालिया में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में समावेशी राजनीति और लोकतांत्रिक चुनाव के महत्व की पुष्टि करते हुए,

सोमालिया में मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, बाढ़, सूखे, टिड्डियों के संक्रमण, जबरन विस्थापन और कोविड-19 से उत्पन्न संयुक्त खतरे को ध्यान में रखते हुए, तथा मानवीय सहायता को सुरक्षित ढंग से पहुंचाने में बाधा डालने वाले किसी भी पक्ष, किसी मानवीय निधि या आपूर्ति के किसी भी प्रकार के विपथन अथवा दुरूपयोग, तथा मानवीय कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा की गतिविधियों या उत्पीड़न की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए,

सोमालिया में यौन और लिंग-आधारित हिंसा के चिंताजनक स्तरों का दस्तावेजीकरण करने वाली रिपोर्टों, महासचिव की रिपोर्ट सहित, को ध्यान में रखते हुए, इसे भी चिंता के साथ ध्यान में रखते हुए कि सोमालिया बच्चों के लिए सबसे घातक युद्ध क्षेत्रों में से एक है, जैसा कि बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की 2021 की रिपोर्ट में उल्लिखित है, अंतरराष्ट्रीय

कानून का उल्लंघन करते हुए सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भर्ती के उच्च स्तर तथा अपहरण के उच्च स्तर को भी चिंता के साथ संज्ञान में लेते हुए, जिसमें अल-शबाब मुख्य अपराधी बना हुआ है, और सोमालिया के अधिकारियों से आग्रह करते हुए कि संकल्प 2467 (2019) के अनुसार उपायों को लागू करने के साथ, बच्चों के विरुद्ध इन "छह गंभीर अपराधों " जैसाकि महासचिव द्वारा चिह्नित किया गया है, के समाधान के प्रयासों को और मजबूत किया जाए,

सोमालिया में स्थिरता के लिए समावेशी संवाद और स्थानीय मध्यस्थता संबंधी प्रक्रियाओं के महत्व को दोहराते हुए , एफजीएस और एफएमएस दोनों के बीच तनाव को कम करने के लिए उन्हें रचनात्मक वार्ता में शामिल करने के महत्व की पुष्टि करते हुए, और यह भी दोहराते हुए कि 2021 में चुनाव को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने से, जैसाकि नियोजित और सम्मत है, सोमालिया अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य समस्याओं पर पुन: ध्यान केंद्रित कर पाएगा जिनमें अल-शबाब द्वारा उत्पन्न खतरा, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी, मानवीय आवश्यकताएं, बाढ़, सूखे और कोविड-19 की समस्याएं शामिल हैं तथा सोमालिया की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने में सभी पक्षों को सक्षम बना पाएगा,

पैनल की अंतिम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, पैनल और एफजीएस के बीच बढ़े हुए सहयोग का स्वागत करते हुए और यह स्मरण करते हुए कि विशेषज्ञों के पैनल सुरक्षा परिषद के अधिदेश के अनुसार काम करते हैं,

देश के पुनर्निर्माण, आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने और हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी को रोकने के प्रयासों में एफजीएस के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए, यह सुनिश्चित करने के अपने इरादे को फिर से व्यक्त करते हुए कि इस संकल्प में दिए गए उपायों एफजीएस को इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाएंगे, यह देखते हुए कि सोमालिया में सुरक्षा की स्थिति में इन उपायों की आवश्यकता बनी हुई है, जिसमें हथियारों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण शामिल है, लेकिन यह पुष्टि करते हुए कि इससे सोमालिया में स्थिति निरंतर समीक्षाधीन रहेगी और यह इस संकल्प में निहित उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें हासिल की गई प्रगति और इस संकल्प के अनुपालन के आलोक में यथावश्यक संशोधन, संभावित बेंचमार्क, निलंबन या उपायों को वापस लेना शामिल है,

संकल्प 2444 (2018) के पैराग्राफ 1 से 8 को स्मरण करते हुए, यह पुनः पुष्टि करते हुए कि यह इरीट्रिया और जिबूती के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से संबंधित घटनाक्रमों पर दृष्टि रखना जारी रखेगा और इन मामलों के सद्भावनापूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों का समर्थन करेगा।

इस संबंध में सोमालिया में राष्ट्र- और शांति-निर्माण के अपने उद्देश्य को रेखांकित करते हुए, जिसमें सोमालिया और इस क्षेत्र में अल-शबाब द्वारा शांति और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को कम करना और अल-शबाब की गतिविधियों के विघटनकारी प्रभाव को कम करना और सोमालिया का सुरक्षा क्षेत्र के सुधारों, विशेष रूप से हथियारों और गोला-बारूद प्रबंधन और और निम्नलिखित परिचालन पैराग्राफ में उल्लिखित उपायों और तंत्रों के माध्यम से समर्थन करना शामिल है,

यह निर्धारित करते हुए कि सोमालिया के हालात इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन कार्य करते हुए,

भाग 1: अल-शबाब के प्रभाव को कम करना

1. यह दोहराते हुए कि अल-शबाब शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और इसकी आतंकवादी एवं अन्य गतिविधियों का सोमालिया और इस क्षेत्र में विघटनकारी प्रभाव पड़ा है, और अल-शबाब के वित्तपोषण को निशाना बनाने, समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सुधार करने, चारकोल की बिक्री सहित अवैध राजस्व सृजन को रोकने तथा आईईडी द्वारा उत्पन्न खतरे को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है;

1क: अवैध वित्तपोषण का निशाना बनाना

2. अल-शबाब की राजस्व और धनशोधन, संसाधनों का भंडारण एवं हस्तांतरण की क्षमता को चिंता के साथ नोट करते हुए, एफजीएस से सोमाली वित्तीय प्राधिकरणों, निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण खतरों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने और उपशमन करने, अनुपालना (अपने ग्राहक को जानें और उपयुक्त अध्यवसायी प्रक्रियाओं सहित) में सुधार के लिए काम जारी रखने का आह्वान करता है और पर्यवेक्षण एवं प्रवर्तन को सुदृढ़ करता है जिसमें सोमालिया के सेंट्रल बैंक और वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एड काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक्ट (2016) और साथ ही मोबाइल मनी रेगुलेशन (2019), के अनुरूप बढ़ी हुई रिपोर्टिंग करना, एक राष्ट्रीय पहचान (आईडी) बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए एफजीएस की सराहना करता है और वित्तीय पहुंच और अनुपालन में सुधार एवं आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए एक प्राथमिकता के मामले के रूप में एक अद्वितीय सोमाली आईडी के विकास को प्रोत्साहित करता है, इसके अलावा, इन खतरों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता लेने को प्रोत्साहित करता है और एफजीएस, यूएनओडीसी और पैनल से अल-शबाब के वित्तपोषण के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान जारी रखने और अल-शबाब के वित्तपोषण को बाधित करने और कानूनी वित्तीय प्रणाली के उपयोग की योजना तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ काम करना जारी रखना शामिल है;

3. एफजीएस से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों, विशेष रूप से इस क्षेत्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संकल्प 1373 (2001), संकल्प 2178 (2014), संकल्प 2462 (2019) और प्रासंगिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन सहित आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का अनुरोध करता है और एफजीएस से अनुरोध करता है कि परिषद को अपनी नियमित रिपोर्टिंग में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए सोमाली प्राधिकारियों द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाइयों पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं;

1ख: समुद्री निषेधाज्ञा और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सुधार

4. समुद्री अपराध संबंधी हिंद महासागर मंच के तहत यूएनओडीसी के वर्तमान अधिदेश के अधीन इसे सोमालिया में अवैध समुद्री दुर्व्यापार पर कार्रवाई करने और आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण करने वाले वैध और अवैध सभी प्रकार के सामानों की तस्करी को बाधित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु यूरोपीय नौसेना बल ऑपरेशन अटलांटा, संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) और इस क्षेत्र में अन्य नौसैनिक बलों सहित प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और तस्करी और अवैध व्यापार में मछली पकड़ने वाले जहाजों की भूमिका सहित एफजीएस और एफएमएस को उनकी समुद्री क्षेत्र जागरूकता और प्रवर्तन में सुधार करने के लिए सहायता करता है;

5. 15 नवंबर 2022 तक संकल्प 2182 (2014) के पैरा 15 में निर्धारित उपबंधों को नवीनीकृत और विस्तारित करने का निर्णय करता है और सदस्य राष्ट्रों को एफजीएस के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर या स्वैच्छिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक भागीदारी जैसे "संयुक्त समुद्री बलों" के माध्यम से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है और जिसे एफजीएस ने महासचिव को अधिसूचित किया है और जिसे महासचिव ने बाद में सभी सदस्य राष्ट्रों को अधिसूचित किया है, ताकि सोमालिया पर हथियारों पर प्रतिबंध के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और वे सोमाली समुद्र क्षेत्रीय जल में और सोमालिया के तट से दूर अरब सागर और फ़ारस की खाड़ी तक फैले हुए समुद्र में सोमालिया आने वाले या वहाँ से जाने वाले जहाजों, जिनके बारे में यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि वे निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न हैं, पर चारकोल प्रतिबंध, और आईईडी कल-पुर्जों पर प्रतिबंध लगाएंगे और बिना किसी अनुचित देरी के निरीक्षण करेंगे:

(i) चारकोल प्रतिबंध के उल्लंघन में सोमालिया से चारकोल ले जाना;

(ii) सोमालिया पर हथियारों के प्रतिबंध के उल्लंघन में सोमालिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हथियार या सैन्य उपकरण ले जाना;

(iii) संकल्प 751 (1992) के अनुसरण में समिति द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों या संस्थाओं को हथियार या सैन्य उपकरण पहुँचाना; अथवा

(iv) आईईडी संघटकों पर प्रतिबंध के उल्लंघन में इस संकल्प के उपाबंध ग के भाग I में चिह्नित आईईडी कल-पुर्जों को ले जाना;

1ग: सोमालिया चारकोल प्रतिबंध

6. सोमालिया से चारकोल के निर्यात संबंधी पूर्ण प्रतिबंध के उल्लंघन में किसी भी निर्यात की निंदा करता है, सोमालिया के चारकोल के आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध के संबंध में अपने निर्णय की पुष्टि करता है जैसा कि इसके संकल्प 2036 (2012) के अनुच्छेद 22 ("चारकोल प्रतिबंध") और संकल्प 2182 (2014) के अनुच्छेद 11 से 21 में निर्दिष्ट किया गया है;

7. सोमालिया से चारकोल के निर्यात को कम करने के लिए एफजीएस, एफएमएस और सदस्य राष्ट्रों द्वारा किए गए उपायों का स्वागत करता है, अपने इस अनुरोध को दोहराते हुए कि सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (एएमआईएसओएम) सोमालिया से चारकोल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने में एफजीएस और एफएमएस को समर्थन और सहायता करता है, घरेलू चारकोल उपयोग के सतत प्रबंधन के विकास के लिए सोमालिया की राष्ट्रीय चारकोल नीति में और बेहतरी करने को प्रोत्साहित करता है, एफजीएस की राष्ट्रीय चारकोल नीति को विकसित करने से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए एफजीएस को घरेलू चारकोल उत्पादन संबंधी आंकड़े और उन्नत विश्लेषण उपलब्ध कराने के के लिए, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को प्रोत्साहित करता है और चारकोल निर्यात करने वाले बंदरगाहों तक पैनल की नियमित पहुंच की सुविधा के लिए एएमआईएसओएम का आह्वान करता है

8. सोमालिया को और सोमालिया से चारकोल के निर्यात और आयात की निगरानी और उसे रोकने के लिए यूएनओडीसी और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के प्रयासों के महत्व की पुष्टि करता है;

1घ: आईईडी संघटक प्रतिबंध

9. अल-शबाब द्वारा किए गए आईईडी हमलों में वृद्धि को देखते हुए, निर्णय लिया कि सभी राष्ट्र इस संकल्प के अनुबंध ग के भाग I में उल्लिखित सामग्री के उनके भूक्षेत्रों से या उनके अपने भूक्षेत्रों के बाहर उनके नागरिकों, या अपने ध्वज जहाजों या विमानों का उपयोग करके सोमालिया को किए जाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरण को रोकेंगे, यदि यह प्रमाणित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि ऐसी सामग्री का उपयोग सोमालिया में तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है या उनके उपयोग से इस तरह का बड़ा जोखिम हो सकता है;

10. यह भी निर्णय करता है कि जब इस संकल्प के अनुबंध ग के भाग I में उल्लिखित कोई सामग्री पैराग्राफ 9 के अनुरूप सोमालिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरित की जाती है, तो संबंधित राष्ट्र ऐसी बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरण के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर समिति को ऐसी बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरण के बारे में अधिसूचित करेगा, और इस अनुच्छेद के अनुसरण में जारी अधिसूचनाओं के महत्व पर बल देता है, जिसमें सामग्री के उपयोग का उद्देश्य, अंतिम उपयोगकर्ता, तकनीकी विनिर्देश और भेजी गई सामग्री की मात्रा सम्मिलित है;

11. सदस्य राष्ट्रों को उनके नागरिकों, उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन व्यक्तियों और उनके भूक्षेत्र में निगमित या उनके अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन फर्म जो सोमालिया में विस्फोटक प्रीकर्सर और सामग्रियों की बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरण में शामिल हैं, जिनका उपयोग उन्नत विस्फोटक उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है, के लिए सतर्कता की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने का आह्वान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एफजीएस के साथ लेनदेन का रिकॉर्ड रखने और सूचना साझा करने के लिए अनुबंध ग के भाग II में उल्लिखित सामग्री शामिल हैं, समिति और पैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि सोमालिया में व्यक्तियों द्वारा इन रसायनों की संदिग्ध खरीद या पूछताछ के संबंध में और इन

सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय स्थापित करने के लिए एफजीएस और एफएमएस को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध हो;

12. एफजीएस विस्फोटक आयुध निपटान दलों के निरंतर विशेषज्ञ प्रशिक्षण और विस्फोटकों के विश्लेषण में सोमाली क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त उपकरण और समन्वय सहायता प्रदान करने के लिए सोमालिया के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय भागीदारों को प्रोत्साहित करता है;

भाग 2: सोमालिया में राष्ट्र को समर्थन-और शांति व्यवस्था

2क: सुरक्षा क्षेत्र में सुधार और अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन

13. एफएमएस के साथ समन्वय में राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे और एसटीपी के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए एफजीएस का आह्वान करता है, और 27 मई 2021 रोडमैप को लागू करने के लिए एफजीएस और एफएमएस से आग्रह करता है;

14. इसके अलावा एफजीएस और एफएमएस से उनके सुरक्षा तंत्र की नागरिक निगरानी बढ़ाने, मानवाधिकारों की समीक्षा सहित सभी रक्षा और सुरक्षा कर्मियों संबंधी उपयुक्त जांच प्रक्रियाओं को अपनाने और लागू करना जारी रखने, और जांच करना और, जैसा उपयुक्त हो, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और युद्ध एवं युद्ध पश्चात् स्थितियों में यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का आह्वान करता है, और इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सोमाली सुरक्षा बलों और एएमआईएसओएम को दिए गए समर्थन के संबंध में महासचिव की मानवाधिकार और उपयुक्त अध्यवसाय की नीति के महत्व को पुनः स्मरण करता है;

15. सोमाली सुरक्षा बलों को विश्वसनीय, पेशेवर और प्रतिनिधि क्षमता वाले बलों के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए एसटीपी के कार्यान्वयन का समर्थन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का *आह्वान करता है*;

16. *सोमालिया* में संघर्षरत सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का आह्वान करता है, और सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप नागरिक हताहतों की सूचना मिलने पर त्वरित और पूर्ण जांच जारी रखने का आग्रह करता है;

2ख: हथियार और गोला बारूद प्रबंधन और सोमालिया में तथा उसके भीतर हथियारों की अवैध आवाजाही को रोकना

17. हथियारों और गोला-बारूद प्रबंधन में हुई प्रगति *का स्वागत करता है और* हथियारों, गोला-बारूद और अन्य सैन्य उपकरणों और उनके वितरण के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन, भंडारण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफजीएस और एफएमएस की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, जिसमें एक ऐसी प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है जिसमें इकाई स्तर पर ऐसे सभी सैन्य उपकरणों और आपूर्ति को ट्रैक करने की व्यवस्था है;

18. यह पुनः *पुष्टि* करता है कि एफजीएस, एफएमएस और एएमआईएसओएम के सहयोग से आक्रामक हमले के हिस्से के रूप में या उनके अधिदेश को पूरा करने के दौरान जब्त किए गए सभी हथियारों और सैन्य उपकरणों का दस्तावेज़ीकरण और पंजीकरण करेगा, जिनमें हथियार और/या गोला-बारूद की प्रकृति और क्रम संख्या को रिकॉर्ड करना, सभी सामग्रियों की फोटोग्राफी करना तथा उन्हें सुसंगत रूप से चिह्नित करना तथा सभी सैन्य साजो-सामानों के पुनः वितरण अथवा उन्हें नष्ट करने से पहले पैनल द्वारा उनके निरीक्षण की सुविधा प्रदान करना शामिल है;

19. एफजीएस और एफएमएस की हथियारों और गोला-बारूद प्रबंधन क्षमता को विकसित करने के लिए अतिरिक्त एवं समन्वित समर्थन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अतिरिक्त और प्रदान करने का आह्वान करता है जिसमें प्रशिक्षण, भंडारण, बुनियादी ढांचे और वितरण के लिए समर्थन, तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस संकल्प की अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी एफजीएस निकायों को सुदृढ़ बनाने में समर्थन के प्रयासों के समन्वय हेतु अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भागीदारों को प्रोत्साहित करता है;

20. इस बात *पर जोर* दिया गया है कि कारगर हथियार और गोला बारूद प्रबंधन से अल-शबाब और अन्य सशस्त्र समूहों की सोमालिया और इस क्षेत्र में हथियार प्राप्त करने की क्षमता घटेगी और इस प्रकार से इससे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा कम होगा और इस बात की पुष्टि करता है कि सभी राष्ट्र सोमालिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए सोमालिया को हथियारों और सैन्य उपकरणों की सभी प्रदायगी पर एक सामान्य और पूर्ण प्रतिबंध लागू रखेंगे, जिसमें सभी प्रकार के हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति और इनके अधिग्रहणों के लिए वित्तपोषण पर रोक लगाना तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी सलाह, वित्तीय और अन्य सहायता देना और सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है, जब तक कि परिषद अन्यथा निर्णय नहीं लेती (जैसा कि इसके संकल्प 733 (1992) और के पैरा 5 और संकल्प 1425 (2002) के पैरा 1 और 2 द्वारा प्रारम्भिक रूप से अधिरोपित किया गया था, इसके बाद "शस्त्र प्रतिबंध" संदर्भित किया गया;

21. यह स्वीकार करते हुये कि एफ़जीएस (एसएसएसआई) तथा सोमाली राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एसएनएसएफ) और सोमाली सुरक्षा क्षेत्र संस्थानों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सोमालिया की राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और एसटीपी के अनुरूप हथियारों और विशेषज्ञ उपकरणों के एक्सेस की आवश्यकता होगी और यह *पुष्टि करते हुये* कि शस्त्र प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होगा:

(1) सोमालियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएनएसएफ के विकास के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, या तकनीकी सलाह, वित्तीय और अन्य सहायता तथा सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, इस संकल्प के अनुबंध क और ख के मदों को छोड़कर, जो इस संकल्प के पैरा 23 और 24 में निर्धारित अनुमोदनों और अधिसूचना प्रक्रियाओं के अध्यधीन हैं;

(2) सोमालियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसएसआई के विकास के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, इस संकल्प के अनुबंध क और ख के मदों को छोड़कर, जो इस संकल्प के पैरा 25 और 26 में निर्धारित अनुमोदनों और अधिसूचना प्रक्रियाओं के अध्यधीन हैं;

(3) सोमालियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसएसआई के विकास के लिए तकनीकी सलाह, वित्तीय और अन्य सहायता तथा सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, जो इस संकल्प के निम्न पैरा 26 में निर्धारित अनुमोदनों और अधिसूचना प्रक्रियाओं के अध्यधीन हैं;

22. *पुष्टि करता है* कि इस संकल्प के पैरा 21 में छूट के अनुसार बेचे या आपूर्ति किए गए हथियारों और सैन्य उपकरणों को ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था या बेचने वाले या आपूर्ति करने वाला राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय संगठन को दोबारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और उनके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जो सोमाली नेशनल सुरक्षा बल या सोमाली सुरक्षा क्षेत्र की संस्था की सेवा में नहीं है, जिसे इन्हें मूल रूप से बेचा या आपूर्ति की गई थी,;

शस्त्र प्रतिबंध के तहत आवश्यक स्वीकृतियां और सूचनाएं

23. पुन: *पुष्टि* करता है कि सोमालियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएनएसएफ के विकास के लिए इस संकल्प के अनुबंध क के अनुसार वस्तुओं की डिलीवरी के लिए मामला-दर-मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अनुरोध एफजीएस या राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन जो सहायता प्रदान करते हैं द्वारा कम से कम पांच कार्य दिवस पहले प्रस्तुत किए जाएंगे;

24. पुन: *पुष्टि* करता है कि सोमालियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएनएसएफ के विकास के लिए इस संकल्प के अनुबंध ख में वस्तुओं की डिलीवरी, एफजीएस या राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन द्वारा सहायता प्रदान करने वाले कम से कम पांच कार्य दिवस पहले प्रस्तुत जानकारी के लिए समिति को अधिसूचना के अधीन हैं;

25. *पुष्टि* करता है कि सोमाली लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसएसआई के विकास के लिए इस संकल्प के अनुबंध क में वस्तुओं की आपुर्ति के लिए मामला-दर-मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अनुरोध आपूर्ति करने वाले राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन द्वारा किया कम से कम पांच कार्य दिवस पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए और राज्यों या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों से *अनुरोध* किया जाता है कि वे ऐसी किसी भी डिलीवरी के लिए समानांतर एफजीएस को अग्रिम में कम से कम पांच कार्य दिवस पहले सूचित करें;

26. *पुष्टि* करता है कि सोमालियाई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसएसआई के विकास के लिए इस संकल्प के लिए अनुबंध ख में वस्तुओं की आपूर्ति या तकनीकी सलाह, वित्तीय और अन्य सहायता और सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण, आपूर्ति करने वाले राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठन से अधिसूचना प्राप्त करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर समिति के नकारात्मक निर्णय की अनुपस्थिति में प्रदान किया जाता है और राष्ट्रों या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों को एफजीएस को कम से कम पांच कार्य दिवस पहले *ऐसी किसी भी आपूर्ति के साथ साथ* सूचित करने का *अनुरोध करता है*;

27. *पुन: पुष्टि* करता है कि केवल मानवीय या सुरक्षात्मक उपयोग के लिए अभिप्रेत गैर-घातक सैन्य उपकरणों की डिलीवरी के विषय में आपूर्ति करने वाले राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन द्वारा समिति को पांच दिन पहले अधिसूचित की जाएगी;

स्वीकृतियों और अधिसूचनाओं के बारे में अधिक जानकारी

28. *पुष्टि* करता है कि एफजीएस का प्राथमिकता है कि वह कम से कम पांच दिन पहले एसएनएसएफ को हथियारों और सैन्य उपकरणों की किसी भी डिलीवरी के लिए अनुच्छेद 23 या 24 के अनुसार समिति से अनुमोदन प्राप्त करे या सूचित करे, और यह कि सभी अनुमोदन और अधिसूचनाओं के अनुरोधों में: हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्माता और आपूर्तिकर्ता का विवरण, प्रकार, कैलिबर और गोला-बारूद सहित हथियारों और गोला-बारूद का विवरण, प्रस्तावित तिथि और वितरण की जगह और एसएनएसएफ में गंतव्य इकाई या भंडारण स्थान की सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए;

29. पुन: *पुष्टि* करता है कि अनुच्छेद 23 या 24 के अनुसरण में एसएनएसएफ को हथियार और सैन्य उपकरण की आपुर्ति करने वाला राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन, वैकल्पिक रूप से, एफजीएस के परामर्श से अनुमोदन या अधिसूचना के लिए अग्रिम अनुरोध कर सकता है, जैसा कि लागू हो, फिर से *पुष्टि करता है* ऐसा करने के लिए चुनने वाले राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन को अनुमोदन या अधिसूचना के लिए अग्रिम अनुरोध के एफजीएस के भीतर उपयुक्त राष्ट्रीय समन्वय निकाय को सूचित करना चाहिए और एफजीएस को अधिसूचना प्रक्रियाओं के साथ तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहिए और समिति से अनुरोध करना चाहिए कि राष्ट्रों या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठनों से अनुमोदन और अधिसूचना के लिए अग्रिम अनुरोध एफजीएस में उपयुक्त राष्ट्रीय समन्वय निकाय को प्रेषित किया जाये;

30. पुन: *पुष्टि* करता है कि अनुच्छेद 25 या 26 के अनुसरण में, एसएसएसआई को किसी भी हथियार और सैन्य उपकरण, तकनीकी सलाह, वित्तीय और अन्य सहायता और सैन्य गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण देने वाले राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन को समिति से अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी है या उसे सूचित करना है, जैसा लागू हो, उन वस्तुओं की किसी भी डिलीवरी, सलाह, सहायता या प्रशिक्षण के लिए और एफजीएस को समानांतर में कम से कम पांच कार्य दिवस पहले सूचित करना और *निर्णय* लेना कि अनुमोदन और अधिसूचना के सभी अनुरोधों में: निर्माता का विवरण और सीरियल नंबर सहित हथियारों और सैन्य उपकरणों के आपूर्तिकर्ता, प्रकार, कैलिबर और गोला-बारूद सहित

हथियारों और गोला-बारूद का विवरण, प्रस्तावित तिथि और डिलीवरी की जगह और इच्छित गंतव्य इकाई, या भंडारण के इच्छित स्थान से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए ;

31. *चिंताजनक रिपोर्ट को नोट करता है* कि राष्ट्र पूर्व प्रस्तावों में निर्धारित अधिसूचना प्रक्रियाओं का पर्याप्त रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रों को अधिसूचना प्रक्रियाओं के अनुसार उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं, जो ऊपर पैरा 23-30 में निर्धारित हैं और आगे राष्ट्रों से एसएसएसआई को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में एफजीएस को सूचित करने सहित सख्ती से इस अधिसूचना का पालन करने का *आग्रह किया है;*

32. *पुष्टि* करता है कि जहां अनुच्छेद 23 या 24 लागू होते हैं वहां एफजीएस हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के 30 दिन तक, एसएनएसएफ को किसी भी आपूर्ति के होने की लिखित पुष्टि के रूप में एक पोस्ट-डिलीवरी अधिसूचना समिति को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए सीरियल नंबर, शिपिंग जानकारी, लदान का बिल, कार्गो मैनिफ़ेस्ट या पैकिंग सूचियाँ और भंडारण का विशिष्ट स्थान शामिल है तथा यह एफ़जीएस के सहयोग से आपूर्ति करने वाले राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन के महत्व को मान्यता देता है;

33. *निर्णय* करता है कि अनुच्छेद 25 या 26 के अंतर्गत आपूर्ति करने वाले राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय संगठन, एसएसएसआई को हथियारों और सैन्य उपकरणों की डिलीवरी के 30 दिनों तक, समिति को एक पोस्ट-डिलीवरी अधिसूचना प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे जिसमें किसी भी आपूर्ति के पूरा होने की लिखित पुष्टि,जिसमें हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए सीरियल नंबर, शिपिंग जानकारी, लदान बिल, कार्गो मैनिफेस्ट या पैकिंग सूची और भंडारण की विशिष्ट जगह शामिल है और इसके साथ साथ एफजीएस को भी सूचित करेंगे;

शस्त्र प्रतिबंध के लिए अतिरिक्त छूट

34. *पुष्टि* करता है कि शस्त्र प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होगा:

(1) सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएसओएम) सहित अफ्रीकी संघ मिशन (एएमआईएसओएम) के सैन्य कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के सहयोग या इनके उपयोग के लिए हथियारों या सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करना या तकनीकी सलाह देना, प्रशिक्षण देना; एएमआईएसओएम के रणनीतिक साझेदार ,जो इसके सहयोग और समन्वय में नवीनतम अफ्रीकी संघ रणनीतिक अवधारणा के संचालन में ही कार्यरत हैं; और संकल्प 2111 (2013) के पैरा 10 (क)- (घ) के अनुसार सोमालिया में यूरोपीय संघ प्रशिक्षण मिशन (ईयूटीएम)

(2) एफजीएस के अनुरोध पर और जिसके लिए एफजीएस ने महासचिव को अधिसूचित किया है, सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती के कृत्यों को रोकने के उपाय करने वाले राष्ट्रों या अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संगठनों के एकमात्र उपयोग के लिए निर्धारित हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, परन्तु किए गए कोई भी उपाय लागू अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून होने के अनुरूप हों;

(3) संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों और मानवीय एवं विकास कार्यकर्ताओं और संबंधित कर्मियों के अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोमालिया को अस्थायी रूप से निर्यात किए गए सुरक्षात्मक कपड़ों की आपूर्ति जिसमें फ्लैक जैकेट और सैन्य हेलमेट शामिल हैं;

(4) रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों को ले जाने वाले जहाजों की अस्थायी यात्राओं के लिए सोमाली बंदरगाहों में प्रवेश, परन्तु ऐसी वस्तुएं हर समय ऐसे जहाज़ों पर मौजूद रहें (जैसा कि पहले संकल्प 2244 (2015) के पैरा 3 द्वारा पुष्टि की गई थी);

भाग 3: लक्षित उपाय

35. अपने संकल्प 1844 (2008) के निर्णयों *जिसके द्वारा* लक्षित प्रतिबंध लगाए गए हैं और संकल्प 2002 (2011) और 2093 (2013) जो सूचीबद्ध मानदंड का विस्तार करते हैं और अपने संकल्प 2060 (2012) और 2444 (2018) के निर्णयों को *स्मरण करता है* और इसके अलावा *स्मरण करता* कि सूचीबद्ध मानदंड में यौन और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित कार्य करने, योजना बनाने, निर्देशित करने या कार्य करने के लिए शामिल है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है और सदस्य राष्ट्रों की जांच में विशेषज्ञों के पैनल की सहायता करने के लिए उनके साथ और एफ़जीएस, एफ़एमएस और एएमआईएसओएम और सहभागियों के साथ, विशेष रूप से अल-शबाब की गतिविधियों, जहां सूचीबद्ध मानदंड द्वारा शामिल किया गया है, के आचरण या उनकी जानकारी साझा करने के लिए अपने अनुरोध को दोहराता है;

36. समिति को संकल्प 1960 (2010) के अनुच्छेद 7 और संकल्प 1998 (2011) के अनुच्छेद 9 के अनुसार बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि से और संघर्ष में यौन हिंसा के लिए विशेष प्रतिनिधि के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए *अनुरोध* करता है और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय को मानवाधिकारों के लिए उपयुक्त प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करता है;

37. पुष्टि करता है कि कहीं भी आयोजित मानवीय सहायता कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके संकल्प 1844 (2008) के अनुच्छेद 3 द्वारा लगाए गए उपाय संयुक्त राष्ट्र, इसकी विशिष्ट एजेंसियां या कार्यक्रमों संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले मानवीय संगठन जो मानवीय सहायता प्रदान करते हैं और उनके कार्यान्वयन में भागीदार द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन, जो सोमालिया के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता योजना में भाग ले रहे हैं द्वारा सोमालिया में तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन, अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के भुगतान पर लागू नहीं होंगे;

सोमालिया पर विशेषज्ञों का पैनल

38. इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से15 दिसंबर 2022 तक, सोमालिया पर पैनल को नवीकृत करने का निर्णय करता है और पैनल के अधिदेश इसके संकल्प 2444 (2018) के पैराग्राफ 11 और के पैराग्राफ 2 में संदर्भित कार्य शामिल होंगे, महासचिव से इसके संकल्प 2467 (2019) के अनुच्छेद 11 के अनुरूप समर्पित महिला पुरुष विशेषज्ञता को शामिल करने का अनुरोध करता है और आगे अनुरोध करता है कि पैनल अपनी जांच और रिपोर्टिंग में जेंडर को एक क्रॉस-कटिंग मुद्दे के रूप में शामिल करे और पैनल के अधिदेश की समीक्षा करे और 15 नवंबर 2022 तक अधिदेश के किसी भी विस्तार के संबंध में उचित कार्रवाई करे;

39. एफजीएस और पैनल के बीच पूर्ण सहयोग के महत्व को स्मरण करता है, हिरासत में लिए गए अल-शबाब और आईएसआईएल के संदिग्ध सदस्यों के पैनल साक्षात्कार की सुविधा के लिए एफजीएस से अनुरोध करता है और दस्तावेज़ एस/2006/997 के अनुरूप अपने आदेश को पूरा करने वाले पैनल के महत्व को नोट करता है तथा पैनल से अनुरोध करता है कि हथियारों में एफजीएस का समर्थन करने के तरीके पर समिति को सिफारिशें और राष्ट्रीय लघु शस्त्र तथा हल्के हथियार आयोग की स्थापना के प्रयासों सहित गोला-बारूद प्रबंधन करे;

40. राष्ट्रों, एफ़जीएस, एफ़एमएस और एएमआईएसओएम के लिए पैनल को जानकारी प्रदान करने और जांच में उनकी सहायता के लिए अपना अनुरोध दोहराता है और सुरक्षा परिषद को इस संकल्प के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए एफ़जीएस और एफ़एमएस से पैनल के लिखित अनुरोध पर एफ़जीएस को मोगदिशु में सभी एफ़जीएस शस्त्रागार, सभी एफ़जीएस -आयातित पैनल की सुविधा, वितरण से पहले हथियार और गोला बारूद, सोमालिया राष्ट्रीय सेना (एसएनए) क्षेत्रों में सभी एफजीएस सैन्य भंडारण सुविधाएं और एफजीएस और एफएमएस के कब्जे वाले हथियार और एफजीएस और एफएमएस के पास मौजूद हथियारों और गोला-बारूद की तस्वीरों और एफजीएस और एफएमएस तक पहुंच की अनुमति देने के लिए और लॉगबुक और वितरण रिकॉर्ड को दिखाने का अनुरोध करता है;

रिपोर्टिंग

41. समिति को नियमित अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए पैनल से अनुरोध करता है, जिसमें शामिल हैं: त्रैमासिक आधार पर कम से कम चार अलग-अलग विषयगत रिपोर्ट दी गई, जिसमें हथियारों और सैन्य उपकरणों की तस्करी, समिति के माध्यम से सुरक्षा परिषद के विचारार्थ एक व्यापक मध्य-अवधि की अद्यतन जानकारी और, 15 अक्टूबर 2022 तक एक अंतिम रिपोर्ट शामिल है और पैनल से उनकी रिपोर्टिंग के निष्कर्षों पर समिति से प्रतिक्रिया लेने का आग्रह करता है ;

42. महासचिव से अनुरोध करता है कि परिषद को 15 सितंबर 2022 से पहले, और सोमालिया के हथियारों और गोला-बारूद प्रबंधन क्षमता के तकनीकी मूल्यांकन को पूरा करने के बाद, इसे और बेहतर बनाने और स्पष्ट एवं यथार्थवादी बेंचमार्क के लिए विकल्पों को स्पष्ट करने के लिए सिफारिशें प्रदान करें जो सुरक्षा परिषद को आज की तारीख तक की गई प्रगति और इस संकल्प के अनुपालन और विशेष रूप से उन उपायों के संभावित संशोधन, निलंबन या इन्हें उठाने पर विचार के आलोक में शस्त्र प्रतिरोध के उपायों की समीक्षा में मार्गदर्शन करने में सहायता कर सकते हैं;

43. सोमालिया में मानवीय सहायता प्रदान करने और सोमालिया में मानवीय सहायता प्रदान करने में किसी भी प्रकार की बाधा पर आपातकालीन राहत समन्वयक से 15 अक्टूबर 2022 तक सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करने का अनुरोध करता है;

44. एफजीएस से अनुरोध करता है कि वह संकल्प 2182 (2014) के पैरा 9 के अनुसार और जैसा कि संकल्प 2244 (2015) के पैरा 7 में अनुरोध किया गया है वह 1 फरवरी 2022 तक और या फिर 1 अगस्त 2022 तक सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अपने सुरक्षा बलों की संरचना, संयोजन, शक्ति और प्रकृति तथा क्षेत्रीय एवं सुरक्षा बलों की स्थिति,

(i) संकल्प 2182 (2014) के पैराग्राफ 7 और संकल्प 2551 (2020) के पैरा 37 में प्रार्थित संयुक्त सत्यापन दल (जेवीटी) की रिपोर्ट;

(ii) आयातित हथियारों और गोला-बारूद के वितरण पर सैन्य उपकरणों के भंडारण के स्थान या एसएनएसएफ में गंतव्य इकाई के बारे में अधिसूचनाओं को शामिल करना;

(ख) घरेलू वित्तीय संस्थानों द्वारा सूचित संदिग्ध गतिविधि का अद्यतन सारांश, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र द्वारा की गई जांच और कार्रवाई;

(ग) जानकारी उपलब्ध होने पर, समिति द्वारा नामित व्यक्तियों की स्थिति पर एक अद्यतन जानकारी;

45. इरिट्रिया और जिबूती के बीच संबंधों के सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर दिनांक 31 जुलाई 2022 के बाद सुरक्षा परिषद को अद्यतन जानकारी उपलब्ध करने के लिए महासचिव से अनुरोध करता है;

46. मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया है।

उपाबंध क

समिति की अग्रिम स्वीकृति के अध्यधीन मदें

1. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जिनमें मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम शामिल हैं (मैनपैड);

2. 12.7 मिमी से अधिक कैलिबर वाले हथियार, और विशेष रूप से इनके लिए डिज़ाइन किए गए घटक, और संबंधित गोला बारूद;

टिप्पणी : (इसमें आरपीजी या एलएडब्लू जैसे कंधे से चलने वाले एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर शामिल नहीं हैं (हल्का एंटी टैंक हथियार), राइफल ग्रनेड, या ग्रनेड लांचर।);

3. 82 मिमी से अधिक कैलिबर के मोर्टार और संबंधित गोला बारूद;

4. एंटी टैंक गाइडेड हथियार, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) और गोला-बारूद तथा इन मदों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए घटक शामिल हैं;

5. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन चार्ज और उपकरण; माइन और संबंधित सामग्री;

6. रात्रि दृष्टि क्षमता वाले हथियार स्थल;

7. सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन या बनाए गए विमान;

टिप्पणी: "विमान" का अर्थ है फिक्स्ड विंग, स्विवल विंग, रोटरी विंग, टिल्ट रोटर या टिल्ट विंग वाहन, या हेलीकॉप्टर।

8. "जहाज" और उभयचर वाहन विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिज़ाइन या बनाए गए वाहन;
टिप्पणी : "पोत" में कोई भी जहाज, सतह पर चलने वाला वाहन, छोटे जलपोत का पोत शामिल है क्षेत्र या हाइड्रोफॉइल और एक पोत के पतवार या पतवार का हिस्सा।

9. मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (संयुक्त राष्ट्र पारंपरिक हथियार रजिस्टर में श्रेणी IV के रूप में सूचीबद्ध)।

उपाबंध ख

सोमाली राष्ट्रीय सुरक्षा बल के लिए उपकरण की सुपुर्दगी के संबंध में अधिसूचना और एफजीएस के अतिरिक्त सोमालिया सुरक्षा क्षेत्र के संस्थानों के लिए समिति का अनुमोदिन

• 12.7 मिमी कैलिबर वाले सभी प्रकार के हथियार: और संबद्ध गोला बारूद;

• आरपीजी-7 और रिकॉइललेस राइफल, और संबंधित गोला बारूद;

• सैन्य मानकों या विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित हेलमेट, या तुलनीय राष्ट्रीय मानक;

• शारीरिक कवच या सुरक्षात्मक वस्त्र, इस प्रकार हैं;

- सेना के मानकों या विनिर्देशों या उनके समकक्ष निर्देशों के अनुसार निर्मित सॉफ्ट बॉडी आर्मर या सुरक्षात्मक वस्त्र;

  टिप्पण : सैन्य मानक या विशिष्टताएं जिसमें विखंडित सुरक्षा के लिए में न्यूनतम विनिर्देश शामिल हैं।

- हार्ड बॉडी आर्मर प्लेट्स जो स्तर III (एनआईजे 0101.06 जुलाई 2008) राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष या इसके बराबर बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करती है;

• सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन या संशोधित जमीन पर चलने वाले वाहन;

• सैन्य उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन या संशोधित संचार उपस्कर

• ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पोजिशनिंग उपकरण, विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए डिज़ाइन या संशोधित।

उपाबंध ग

विस्फोटक युक्ति (आईईडी) घटक विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक प्रवर्तक, विस्फोटक संबंधित उपस्कर और संबंधित प्रौद्योगिकी
भाग I

1. विस्फोटक सामग्री, और जिसमें एक या इससे अधिक मिश्रण निम्नानुसार शामिल है :

क. नाइट्रोसेल्यूलोज (12.5% से अधिक नाइट्रोजन डब्लू/ डब्लू युक्त);

ख. ट्राईनाइट्रोफेनिलमिथाइलनाइट्रामाइन (टेट्रिल);

ग. नाइट्रोग्लिसरीन (एकल औषधीय खुराक में पैक/तैयार करने के अतिरिक्त)

2. विस्फोटक से संबंधित सामग्री :

क. उपस्कर और डिवाइज जो विशेष रूप से विद्युत या गैर-विद्युत वाले विस्फोटक शुरू करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं (जैसे फायरिंग सेट, डेटोनेटर, इग्नाइटर, डेटोनिंग कार्ड)।

3. पैरा 1 और 2 में सूचीबद्ध वस्तुओं के "उत्पादन" या "उपयोग" के लिए आवश्यक "प्रौद्योगिकी"।

भाग II

1. विस्फोटक सामग्री, और उसमें शामिल एक या अधिक मिश्रण निम्नानुसार हैं:

क. अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल (एएनएफओ);

ख. नाइट्रोग्लाइकॉल;

ग. पेंटाइरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (पीईटीएन);

घ. पिक्रिल क्लोराइड;

ड. 2,4,6-ट्रिनिट्रोटोलुइन (टीएनटी)।

2. विस्फोटक प्रवर्तक:

क. अमोनियम नाइट्रेट;

ख. पोटेशियम नाइट्रेट;

ग. सोडियम क्लोरेट;

घ. नाइट्रिक एसिड;

ड. सलफेट एसिड।

उपाबंध 7

संकल्प 2628 (2022)

सुरक्षा परिषद द्वारा तारीख 31 मार्च 2022 की 9009 बैठक में अंगीकार किया गया

सुरक्षा परिषद,

सोमालिया की स्थिति पर राष्ट्रपति के पिछले संकल्पों और बयानों को दोहराते हुए, और सोमालिय की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एकता के लिए अपने सम्मान की पुष्टि करते हुए,

यह दोहराते हुए कि सोमालिया की संघीय सरकार (एफजीएस) की प्राथमिक जिम्मेदारी सोमालिया में सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और सोमालिया के सुरक्षित, स्थिर, शांतिपूर्ण, एकजुट और लोकतांत्रिक देश के अपने लक्ष्य को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए।

इस बात पर बल देते हुए कि सोमालिया द्वारा सोमालिया संक्रमण योजना (एसटीपी), और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे (एनएसए) के अधीन निर्धारित दिशा में रणनीति के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए और सोमालिया में स्थिरता एवं राष्ट्र-निर्माण प्रक्रियाओं के समर्थन में सभी हितधारकों के बीच अधिक साझेदारी और समन्वय का आग्रह करते हुए ,

सोमालिया में पहली बार 15 साल पहले अधिकृत होने से अब तक स्थायी शांति और स्थिरता का निर्माण करने के लिए अफ्रीकी संघ मिशन (एएमआईएसओएम) के योगदान की सराहना करते हुए, और मिशन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एएमआईएसओएम के सभी कर्मियों और सोमाली सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि देते हुए,

सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यालय (यूएनएसओएस) द्वारा एएमआईएसओएम को प्रदान किए गए समर्थन का स्वागत करते हुए, यूरोपीय संघ और अन्य दाताओं द्वारा एएमआईएसओएम को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की सराहना करते हुए, और सदस्य राज्यों द्वारा सोमालिया को प्रदान किए गए द्विपक्षीय समर्थन को ध्यान में रखते हुए,

यह स्वीकार करते हुए कि सोमालिया में सुरक्षा की स्थिति में काफी बदलाव आया है क्योंकि एएमआईएसओएम को पहली बार अधिकृत किया गया था, और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का जवाब देने के लिए सोमालिया की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार को ध्यान में रखते हुए,

लागू अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्य दायित्वों के अनुसार सभी साधनों द्वारा आतंकवाद के खतरों से लड़ने की आवश्यकता की पुन: पुष्टि करते हुए, और इस बात की पुन: पुष्टि करते हुए कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य, उनकी प्रेरणाओं के बावजूद, जब भी, कहीं भी और किसी भी के द्वारा किया गया हो, वह आपराधिक और अनुचित है,

इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि अल-शबाब सोमालिया और क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए निरंतर रूप से एक गंभीर खतरा बना हुआ है, और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) के बढ़ते उपयोग और कानूनी वित्तीय प्रणाली के दुरूपयोग को देखते हुए,

सोमालिया में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट (आईएसआईएल को द-एश के नाम से भी जाना जाता है) से जुड़े सहयोगियों की निरंतर उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए,

यह स्वीकार करते हुए कि अल-शबाब द्वारा उत्पन्न खतरा बढ़ गया है, और सोमालिया को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को आज तक हासिल सुरक्षा लाभ को समेकित करने के लिए अनुकूलित करना चाहिए और एक अधिक स्थिर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण सोमालिया की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करना चाहिए,

सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन के पुनर्गठन की आवश्यकता को दोहराते हुए, जो सोमालिया को अपनी सुरक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी लेने में समर्थ और सक्षम बनने पर केंद्रित है, और भविष्य के मिशन के आकार के बारे में निर्णय लेने, जिसमें इसकी रसद आवश्यकताएं शामिल हैं, के लिए एसटीपी और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से एएमआईएसओएम के अभियान की अवधारणा (सीओएनओपीएस) के अद्यतन हेतु सोमालिया और अफ्रीका संघ के संयुक्त प्रयास की प्रशंसा व्यक्त करते हुए।

संकल्प 2568 (2021) (जिसे इसमें इसके पश्चात संयुक्त प्रस्ताव कहा गया है) में किए गए अनुरोध अनुसार महासचिव द्वारा 7 मार्च 2022 को सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत किए गए, और सोमालिया में एक पुन: कॉन्फ़िगर अफ्रीकी संघ मिशन के रणनीतिक उद्देश्यों, आकार और संरचना के लिए एफजीएस और दाताओं के परामर्श से अफ्रीकी संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की सराहना करते हुए,

8 मार्च 2022 को अफ्रीकी संघ शांति और सुरक्षा परिषद की अपनी 1068वीं बैठक की विज्ञप्ति, और सोमालिया में एएमआईएसओएम को अफ्रीकी यूनियन ट्रांजिशन मिशन (एटीएमआईएस) के रूप में पुनर्विचारित करने के अपने निर्णय को *ध्यान में रखते हुए,*

अफ्रीकी संघ द्वारा तैनात सैन्य टुकड़ियों तथा पुलिस दल और सोमालिया के बल निर्माण तथा एकीकरण के प्रयासों, दोनों के बीच मजबूत कमान और नियंत्रण और परिचालन समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर *बल देते हुए;*

एकीकृत सोमाली सुरक्षा बलों और संस्थानों को सुरक्षा खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए क्षमता निर्माण और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के महत्व पर *बल देते हुए,* और क्षमता निर्माण और सुरक्षा सुधार का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एफजीएस, सोमालिया के संघीय सदस्य राज्यों (एफएमएस), संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ, और सोमालिया के अंतरराष्ट्रीय

साझेदार के बीच समन्वय के महत्व और सोमालिया को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाने पर *अधिक बल देते हुए,*

यह स्वीकार करते हुए कि सोमालिया में शांति और सुरक्षा के लिए खतरों का समाधान करने के लिए अकेले सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, इस बात पर *बल देते हुए* कि स्थायी शांति के निर्माण के लिए नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, और शांति तथा स्थिरता की नींव को मजबूत करने वाले समग्र दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराने के साथ सोमालिया द्वारा परिभाषित प्राथमिकताओं में निम्न भी शामिल हैं:

(i) प्रभावी शासन और लोक प्रशासन,

(ii) भ्रष्टाचार विरोधी,

(iii) संगठित अपराध को रोकना,

(iv) कानून का शासन,

(v) न्याय और कानून प्रवर्तन,

(vi) आतंकवाद की रोकथाम करने के प्रयास,

(vii) आतंकवादी विघटन और दलबदल को बढ़ावा देने के प्रयास,

(viii) आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हिंसक कट्टरवाद को रोकना और उसका मुकाबला करना,

(ix) सुरक्षा क्षेत्र में सुधार, और

(x) समावेशी राजनीति और सुलह,

सोमालिया में शांति निर्माण और संघर्षोपरांत पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन, यदि सोमालिया के प्राधिकारियों द्वारा परिभाषित प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदान किया जाता है, की संभावना को देखते हुए, और इस संबंध में अफ्रीकी संघ संघर्षोपरांत पुनर्निर्माण और विकास (एयूपीसीआरडी) नीति और काहिरा में एयूपीसीआरडी समर्पित केंद्र को आगे ध्यान में रखते हुए,

समावेशी राजनीतिक समझौतों पर पंहुच रहे एफजीएस और एफएमएस के विशिष्ट महत्व को रेखांकित करते हुए, सुरक्षा और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर सहयोग का आग्रह करते हुए, सभी दलों द्वारा सहयोग में सुधार की जिम्मेदारियों और सभी सोमालियों के लाभ के लिए चर्चा में शामिल होना, और यह देखते हुए कि सभी दलों का पूर्ण सहयोग निम्नलिखित के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की प्रगति को आगे बढ़ाएगा:

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला का कार्यान्वयन,

(ii) एसटीपी का कार्यान्वयन,

(iii) पूरी तरह से कार्यशील संघीय व्यवस्था सुनिश्चित करना, और

(iv) सोमालिया की सरकार और संस्थानों के लिए कानूनी और राजनीतिक आधार के रूप में संविधान को अंतिम रूप देना,

इस संबंध में सोमालिया (यूएनएसओएम) में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन द्वारा प्रदान की गई सहायता का *स्वागत करते हुए,* और वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद यूएनएसओएम की रणनीतिक समीक्षा के लिए संकल्प 2592 (2021) में अपने अनुरोध को *याद करते हुए,*

ध्यान देते हुए कि यूएनएसओएम और एटीएमआईएस के पास सोमालिया में शांति और सुलह का समर्थन करने के लिए पूरक जनादेश हैं, और यह कि एटीएमआईएस सोमालिया की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करके और सुरक्षा प्रदान करके न्याय, स्थानीय शासन, शांति और सुलह में महत्वपूर्ण योगदान देगा,

संयुक्त राष्ट्र पैनल के विशेषज्ञों द्वारा सोमालिया के लिए किए गए पूरक कार्य और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की भूमिका, अन्य बातों के अलावा, सोमालिया और सोमालियाई क्षेत्र गैर-सैन्य तरीकों द्वारा अल-शबाब की गतिविधियों के अस्थिर प्रभाव को कम करने और सुरक्षा क्षेत्र में, विशेष रूप से हथियार और गोला बारूद प्रबंधन, सुधार के लिए सोमालिया का समर्थन करने को *मान्यता देते हुए,*

सोमाली महिला चार्टर के संकल्प 1325 (2000) और उसके बाद के प्रस्तावों में परिकल्पित संघर्षों की रोकथाम और समाधान तथा शांति निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, और शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर सभी प्रयासों में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए, और संघर्ष की रोकथाम और समाधान के संबंध में निर्णय लेने और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता *को याद करते हुए,*

सोमालिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा हनन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की *निंदा* करते हुए, सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अधीन अपने दायित्वों के पूर्ण अनुपालन के लिए कार्य करने का *आह्वान करते हुए,*

सोमालिया में मानवीय स्थिति के बारे में गंभीर चिंता *व्यक्त करते हुए* संघर्ष के सभी पक्षकारों से लागू अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के संबंद्ध प्रावधानों के अनुसार तथा मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता सहित संयुक्त राष्ट्र के मानवीय आपदा सहायता मार्गदर्शन सिद्धांतों (संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प, 46/182) के अनुरूप तरीकों से सोमालिया के समर्थन के लिए आवश्यक मानवीय सहायता प्रावधानों को लागू करना और सुविधाजनक बनाना,

सोमालिया के जलवायु परिवर्तन, अन्य पारिस्थितिक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और सोमालिया की स्थिरता पर अन्य कारकों पर एफजीएस और संयुक्त राष्ट्र की पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर *जोर देते हुए,*

यह निर्धारित करते हुए कि सोमालिया की स्थिति क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन *कार्य कर रहा है,*

सोमालिया

1. 27 सितंबर 2020, 27 मई 2021 और 09 जनवरी 2022 को हुए समझौतों का स्वागत करता है, और एफजीएस और एफएमएस से इन समझौतों के कार्यान्वयन पर किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक हल करने का आग्रह करता है ताकि चुनावी प्रक्रिया को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सके, और यह *रेखांकित करता है* कि चुनावी प्रक्रिया का पूरा होना और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्राप्त होना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की प्रगति में मदद करेगा और एसटीपी तथा एनएसए के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता के परिवर्तन का समर्थन करेगा;

2. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रगति के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें शामिल हैं: एनएसए, एसटीपी, नौवीं राष्ट्रीय विकास योजना, एक संघीय पुलिस और न्याय प्रणाली पर समझौता, वित्तीय संघवाद, शक्ति और संसाधन-साझाकरण, संवैधानिक समीक्षा, और स्थानीय और राष्ट्रीय सुलह, और इस संबंध में 27 मई 2021 को सहमत रोडमैप का स्वागत करता है, और सोमालिया से बिना देरी के इसे लागू करने का आग्रह करता है;

3. महिलाओं की पूर्ण, समान, सार्थक और प्रभावी भागीदारी के महत्व की *पुष्टि करता है,* और सभी सोमालियाई नागरिकों, जिसमें युवा, विकलांग व्यक्ति, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) और शरणार्थी शामिल हैं, को

संघर्षों के रोकथाम एवं समाधान, सुलह प्रक्रियाओं, शांति निर्माण और चुनाव तथा अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को शामिल करता है, और इस संबंध में सिविल सोसायटी द्वारा किए जा सकने वाले योगदान को स्वीकार करता है और सोमालिया से नागरिक समाज संगठनों को स्वतंत्र रूप से काम करने और उन्हें खतरों और प्रतिशोध से बचाने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का आह्वान करता है;

4. सोमालिया को अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाने के अपने उद्देश्य को *दोहराता है*, जिसमें अल-शबाब द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने और उसे निपटाने में अग्रणी भूमिका शामिल है, जिसमें अल-शबाब की क्षमताओं को कम करने के लिए सैन्य अभियानों के संचालन शामिल हैं, और सोमालिया से *दृढ़तापूर्वक आग्रह करता है* कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रदान किए गए अवसर और समर्थन का उपयोग कर एसटीपी और एनएसए का कार्यान्वयन और जवाबदेह, सस्ती और सक्षम सुरक्षा बलों के निर्माण को प्राथमिकता दे ताकि एटीएमआईएस अपने चरणबद्ध गिरावट को जारी रख सके, और सोमालिया अपनी सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी ले सके;

5. एसटीपी और एनएसए का प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए सोमालियाई अधिकारियों से *आह्वान* उचित रूप से संसाधित है, जिसमें आवश्यक लॉजिस्टिक समर्थन क्षमताओं के विकास के साथ-साथ एटीएमआईएस के साथ कमांड, नियंत्रण और योजना के प्रचालन हेतु समन्वय तंत्र, संयुक्त ऑपरेशनों का संचालन और कार्यान्वयन शामिल है।

6. सोमाली प्राधिकरणों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी को *रेखांकित* करता है, और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा के महत्व को *आगे रेखांकित* करता है;

7. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समन्वित समर्थन से सोमाली अधिकारियों से *आह्वान*, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरोत्तर अधिक जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए, और नए सुरक्षा बलों के निर्माण के लिए एक रणनीतिक योजना को विकसित करने और लागू करने के लिए, जहां उपयुक्त हो, मौजूदा बलों को एकीकृत करने के लिए, और वर्तमान और नव निर्मित सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और सज्जित करने के लिए, स्पष्ट लक्ष्यों और समय-सीमा के साथ और इस संबंध में, एफजीएस के निम्न सुरक्षा बलों के निर्माण के इरादों का स्वागत करता है-

(क) दिसंबर 2022 तक 3850 सुरक्षा बल;

(ख) सितंबर 2023 तक 8525 सुरक्षा बल;

(ग) जून 2024 तक 10450 सुरक्षा बल;

8. बढ़ी हुई क्षमता और योग्यताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त प्रस्ताव और सीओएनओपी के अनुकूल समय सीमा के भीतर, क्षेत्रीय बलों के निर्माण और एकीकरण की प्रक्रिया पर एफजीएस द्वारा एफएमएस के साथ काम करने का आह्वान करता है;

9. सोमाली अधिकारियों से नागरिक निगरानी बढ़ाने और उनके सुरक्षा तंत्र की जवाबदेही और मानवाधिकारों की पुनरीक्षा सहित सभी रक्षा और सुरक्षा कर्मियों की उचित जांच प्रक्रियाओं को अपनाना और लागू करना जारी रखने का आह्वान करता है;

10. चुनावों के स्थायीकरण और तैयार और संचालन में पुलिस और न्याय क्षेत्र की आवश्यक भूमिका की *पुष्टि करता है*, सोमालिया से प्रभावी प्रशिक्षण, उपकरणों के प्रावधान और निरंतर समर्थन के माध्यम से राज्य और संघीय पुलिस का पूरी तरह से समर्थन करने का *आह्वान करता है*, क्षेत्र को सुरक्षित रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराता है और, नागरिक आबादी के लिए सुरक्षा प्रदान करने में योग्य एक पेशेवर और सक्षम पुलिस बल, जो एसटीपी और एनएसए को पूरी तरह से लागू करने हेतु सोमालिया के लिए आवश्यक है, *पर जोर देता है*, और सोमाली समाज के सभी वर्गों से समावेशी और प्रतिनिधि सोमाली सुरक्षा और पुलिस बल की भर्ती को *प्रोत्साहित करता है*;

11. सोमालिया से यह सुनिश्चित करने का *आह्वान करता है* कि सभी सुरक्षा और पुलिस बल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरी तरह से सम्मान करें और यह सुनिश्चित करें कि मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए, इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, अफ्रीकी संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से सोमाली अधिकारियों का उचित समर्थन करने के लिए *आह्वान करता है* और *अनुरोध करता है* कि एटीएमआईएस नागरिक हताहत ट्रैकिंग विश्लेषण और प्रतिक्रिया सेल (सीसीटीएआरसी) के संचालन से सीखे गए अनुभव और सबक को राष्ट्रीय प्राधिकारियों के साथ साझा करे, जिसमें सोमाली नागरिक हताहत निगरानी, शमन, और रोकथाम नीतियों और तंत्रों के विकास का समर्थन भी शामिल हो;

12. यूएनएमएएस सहित, एटीएमआईएस, अंतरराष्ट्रीय भागीदारों और सुसंगत संयुक्त राष्ट्र इकाईयों के साथ समन्वय से सोमालिया के प्राधिकारियों ने छोटे हथियारों और हल्के शस्त्रों के अवैध व्यापार, अंतरण, दुरुपयोग और संग्रहण, और सोमालिया में सभी प्रकार के विस्फोटकों और संबंधित सामग्रियों की अनधिकृत प्राप्तकर्ताओं तक पंहुच को रोकने और उनकी सुरक्षा तथा प्रभावी प्रबंधन एवं भण्डारण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया;

13. एटीएमआईएस से सोमालिया तक सुरक्षा जिम्मेदारियों के बदलाव के दौरान हर एक जगह की सुरक्षा स्थिति पर विचार करने के लिए सोमालिया और उसके अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और बल देता हे कि नियोजन तथा निर्णय नागरिकों को धमकी के एक व्यापक मूल्यांकन द्वारा लिया जाना चाहिए और सैन्य कार्रवाई के दौरान और इसके पश्चात जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी उपाय, जिसमें पहले सुरक्षा और हिफाजत निरंतर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आकार, योग्य और जवाबदेह सीमा की सुरक्षा और पुलिस बल की उपस्थिति स्थापित करना शामिल है, किए जाने चाहिए;

14. संकल्प 1612 (2005) और बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष पर उसके बाद के संकल्पों को याद करते हुए और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ हत्या, अपांगन, बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य प्रकारों के साथ-साथ गैरकानूनी भर्ती और गैर-लड़ाकू भूमिकाओं सहित उनके उपयोग, पुनः भर्ती, और बच्चों के अपहरण की रिपोर्टों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सोमाली प्राधिकारियों से निम्नलिखित का आवाहन करता है:

(क) बाल संरक्षण पर कानूनी ढांचे को मजबूत करना और बाल संरक्षण पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करना;

(ख) बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने और इसके जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराने के लिए कार्रवाई करना;

(ग) स्कूलों और अस्पतालों सहित नागरिक अवसंवरचना के खिलाफ हमलों को रोकने और उनके सैन्य उपयोग को रोकने के लिए उचित उपाय करना;

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों में उन सभी बच्चों की नजरबंदी को रोकना जहां लागू अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा हो और इसके बजाय बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अधीन सोमालिया के दायित्वों के अनुरूप बच्चों के साथ प्राथमिक तौर पर पीड़ित के रूप में व्यवहार करना; तथा

(ङ) 2012 की अपनी कार्य योजनाओं, सशस्त्र समूहों से अलग हुए बच्चों को सौंपने के लिए 2014 की मानक संचालन प्रक्रियाओं, 2018 रोडमैप और सोमालिया में बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष पर कार्य समूह के निष्कर्षों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई करना (एस/एसी.51/ 2020/6);

15. सोमालिया में सशस्त्र संघर्ष में शामिल सभी दलों को यौन और महिला/पुरुष आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए आह्वान करना और आगे सोमाली प्राधिकारियों को निम्नलिखित के लिए संबंधित भागीदारों के साथ काम करने का आह्वान करना:

(क) सभी के लिए यौन और महिला/पुरुष आधारित हिंसा, और संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ख) यौन और महिला/पुरुष आधारित हिंसा को रोकने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए जीवनरक्षा-केंद्रित और लिंग- एवं उम्र-संवेदनशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करना;

(ग) कथित दुर्व्यवहारों की जांच के लिए उचित कदम उठाना और दण्ड से मुक्ति को रोकने के लिए कथित अपराधियों पर मुकदमा चलना;

(घ) संकल्प 2467 (2019) और अन्य प्रासंगिक संकल्पों के अनुरूप जवाबदेही का समर्थन करने के लिए कानून को मजबूत करना; तथा

(ङ) संघर्ष में यौन हिंसा की रोकथाम और प्रतिक्रिया पर संयुक्त विज्ञप्ति और राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाना;

16. स्कूलों और स्कूलों से जुड़े नागरिकों के खिलाफ हमलों और हमलों की धमकी, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में है, की कड़ी निंदा करना और सशस्त्र संघर्ष के सभी दलों से ऐसे हमलों और हमलों की धमकियों को तुरंत बंद करने और शिक्षा में बाधा डालने वाले कार्यों को करने से बचने का आग्रह करना;

17. अपने संकल्प 2417 (2018) को याद करना और सोमालिया में चल रहे मानवीय संकट और सोमालिया के लोगों पर इसके प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करना, दानकर्ताओं सहित सभी भागीदारों को 2022 में मानवीय सहायता प्रदान करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना, अल-शबाब सहित अन्य द्वारा मानवीय और चिकित्सा कर्मियों तथा नागरिक अवसंवरचना के खिलाफ किसी अविवेकपूर्ण या प्रत्यक्ष हमले, और साथ ही मानवीय सहायता के किसी भी दुरुपयोग या उसमें बाधा डालने की कड़ी निंदा करना, अंतरराष्ट्रीय कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार और मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप, पूरे सोमालिया में जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी पक्षकारों को पूर्ण, सुरक्षित, तीव्र और निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने की अपनी मांग को दोहराता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता के उचित लेखांकन के महत्व को रेखांकित करना;

अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े सहयोगी

18. अल-शबाब द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले हमलों और सोमालिया तथा व्यापक क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों, नागरिकों और नागरिक अवसंवरचना के खिलाफ इसके आतंकवादी हमलों के साथ-साथ नागरिकों को बंधक बनाने और अपहरण, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों के उपयोग की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करना और चिंता व्यक्त करता है कि ये गतिविधियाँ सोमालिया में शांति और सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, एकीकरण और विकास के लिए खतरा हैं, और मानवीय पीड़ा को बढ़ाती हैं;

19. यह दोहराता है कि सोमालिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एफजीएस की है, और अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े सहयोगियों का व्यापक तरीके से मुकाबला करने के प्रयासों को प्राथमिकता देने, उसका समन्वय करने और उसे मजबूत करने के लिए सोमालिया से आह्वान करता है, जिसमें यथालागू अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन अपने दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में, सैन्य अभियानों

के उपयोग के माध्यम से उनकी क्षमताओं को कम करना और वित्तीय संसाधनों, हथियारों और गोला-बारूद तक पहुंचने की उनकी क्षमता को बाधित करना शामिल है परंतु यह प्रयास यहीं तक सीमित नहीं होंगे;

20. यह पुनःपुष्टि करता है कि सभी राष्ट्र आतंकवादी कृत्यों को रोकेंगे और उसका अंत करेंगे, सभी राज्यों से यह आग्रह करता है कि वे आतंकवाद से निपटने वाले अभिसमय के साथ-साथ संकल्प 1373 (2001) सहित लागू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों के अनुसार सोमालिया में अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और आगे यह पुष्टि करता है कि सदस्य राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किए गए कोई भी उपाय संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन अन्य सभी दायित्वों के अनुरूप होंगे;

21. सोमालिया से संकल्प 1373 (2001), संकल्प 2178 (2014), संकल्प 2462 (2019) का अनुपालन सहित आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए अन्य सदस्य राष्ट्रों, विशेष रूप से क्षेत्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का अनुरोध करता है, और सोमालिया से अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सदस्य राष्ट्रों के समर्थन से अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े संगठनों को कमजोर करने के लिए गैर-सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता है, ताकि उन्हें सोमालिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एकता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों का संचालन करने से रोका जा सके, उनकी आतंकवादी गतिविधियों, अवैध वित्त, संगठित अपराध, बंदूकों और हल्के हथियारों सहित हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी, आईईडी निर्माण, न्याय और प्रचार गतिविधियों का विरोध किया जा सके, और 2607 (2021) में निर्धारित उपायों को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम किया जा सके, जिसमें संकल्प 751 (1992) के अनुसार सुरक्षा परिषद समिति द्वारा नामित व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ लगाए गए उपाय शामिल हैं;

एटीएमआईएस

22. सोमालिया (एटीएमआईएस) में अफ्रीकी संघ परिवर्तन मिशन में एएमआईएसओएम को पुन: कॉन्फ़िगर करने के अफ्रीकी संघ शांति और सुरक्षा परिषद के निर्णय का समर्थन करता है, और 12 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए, अफ्रीकी संघ के सदस्य राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन भाग लेने वाले राज्यों के दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में, और सोमालिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एकता के पूर्ण सम्मान में निम्नलिखित के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकृत करता है:

(क) अल-शबाब द्वारा उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए अपने अधिदेश को पूरा करना;

(ख) एकीकृत सोमाली सुरक्षा और पुलिस बलों की क्षमता निर्माण का समर्थन;

(ग) सोमालिया को चरणबद्ध रूप से सुरक्षा उत्तरदायित्व सौंपना; तथा

(घ) सोमालिया में एसटीपी और एनएसए के अनुरूप, एक स्थिर, संघीय, संप्रभु और संयुक्त सोमालिया के विकास के समर्थन में शांति और सुलह प्रयासों का समर्थन करना;

23. संयुक्त प्रस्ताव में उल्लिखित निम्नलिखित रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एटीएमआईएस को अधिकृत करने का निर्णय लेता है:

(क) अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े संगठनों को कमजोर करने के लिए सोमाली सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त रूप से नियोजित और लक्षित अभियान चलाना;

(ख) प्राथमिकता वाले जनसंख्या केंद्रों को संयुक्त रूप से आयोजित करके और स्थानीय समुदायों, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा प्रदान करके, एफजीएस द्वारा पहचाने गए मुख्य आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करके, और सोमाली राष्ट्रीय स्थिरीकरण रणनीति और राष्ट्र स्थिरीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सोमाली सुरक्षा बलों के सहयोग से स्थिरीकरण और सुलह सहभागियों के साथ समन्वय करके सोमाली सुरक्षा बलों का समर्थन करना;

(ग) सामुदायिक वसूली और राज्य प्राधिकरण के विस्तार और जवाबदेही (क्रेस्टा/ए) और अन्य स्थिरीकरण सहायकों के समन्वय में सभी बरामद क्षेत्रों के लिए स्थिरीकरण प्रयासों के कार्यान्वयन में एफजीएस की सहायता करना;

(घ) सोमालिया में सुरक्षा जिम्मेदारियों के प्रगतिशील अधिग्रहण की सुविधा के लिए बल उत्पादन, परिचालन दक्षताओं और सैन्य समर्थन क्षमताओं को प्राथमिकता के साथ सोमाली सुरक्षा बलों के क्षमता विकास का समर्थन करना;

(ङ) एसटीपी के अनुरूप, और संघीय सरकारी संस्थानों के सहयोग से मानवीय संपर्क, सामुदायिक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाकर और साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करने के लिए सोमाली सुरक्षा बलों की सहायता करके और इसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराकर सोमाली सुरक्षा बलों को स्पष्ट, अधिकार और निर्माण चरणों में समर्थन करना;

24. संयुक्त प्रस्ताव के पैरा 33 से 39 में उल्लिखित कार्यों के संचालन के लिए एटीएमआईएस के सैन्य, पुलिस और नागरिक घटकों को अधिकृत करने का निर्णय लेता है, और स्मरण करता है कि सीओएनओपी निम्नलिखित कार्य प्रदान करता है:

(क) अल-शबाब और आईएसआईएल से जुड़े संगठनों को कमजोर करने के लिए सोमाली सुरक्षा बलों के समन्वय में, सभी क्षेत्रों में एक साथ लक्षित आक्रामक अभियान चलाना;

(ख) स्थिरीकरण प्रयासों, सुलह और शांति निर्माण सहित सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया के लिए सुरक्षा प्रदान करने में सोमाली सुरक्षा बलों का समर्थन करना;

(ग) सोमाली सुरक्षा बलों को सुरक्षा जिम्मेदारी सौंपने का सर्वोत्तम समर्थन करने के लिए संयोजन, संरचना, स्वभाव और उपकरण के संदर्भ में एटीएमआईएस को कॉन्फ़िगर करना;

(घ) अल-शबाब से बरामद क्षेत्रों सहित मुख्य आपूर्ति मार्गों को साफ करने में सोमाली सुरक्षा बलों का समर्थन करना; सोमाली राष्ट्रीय सेना को युद्ध परामर्श प्रदान करना; नागरिक-सैन्य समन्वय गतिविधियों का संचालन करने के लिए सोमाली राष्ट्रीय सेना की क्षमता में वृद्धि करना;

(ङ) संयुक्त रूप से भागीदारों के साथ, काउंटर इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों के संचालन के लिए सोमाली राष्ट्रीय सेना की क्षमता में वृद्धि करना;

(च) संपर्क के नियमों, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और सभी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(छ) सोमाली परिवर्तन योजना के अनुरूप सोमाली पुलिस को विशेष प्रशिक्षण, परामर्श और सलाह देना और संयुक्त गश्त और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सहित परिचालन सहायता प्रदान करना;

(ज) पुलिस निर्माण और तैनाती के माध्यम से सोमालिया में पुलिस सेवाओं के प्रावधान में सोमाली पुलिस की सेवा वितरण क्षमता का समर्थन करना;

(झ) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के माध्यम से हिंसा के प्रति कट्टरता, आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद और सामाजिक अव्यवस्था के लिए पुलिस-सार्वजनिक भागीदारी का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, महिला शांति और सुरक्षा संकल्प और आचरण और अनुशासन मानकों के अनुपालन में सोमाली पुलिस बलों के प्रयासों का समर्थन करना;

(ञ) एटीएमआईएस संचालन के स्पष्ट-होल्ड-बिल्ड चरणों में, एटीएमआईएस वर्दीधारी घटकों के साथ-साथ एटीएमआईएस के साथ संयुक्त रूप से संचालित सोमाली सुरक्षा बलों का समर्थन करने के लिए गतिविधियों का संचालन करना, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अधीन दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में और गैर-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बलों को संयुक्त राष्ट्र समर्थन पर मानवाधिकारों के कारण परिश्रम नीति (एचआरडीडीपी) के अनुपालन में, साथ ही साथ शांति समर्थन संचालन के लिए अफ्रीकी संघ अनुपालन और जवाबदेही ढांचे के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करना;

(ट) नए बरामद क्षेत्रों और मानवीय संपर्क में शीघ्र वसूली की पहल का समर्थन करना;

(ठ) सोमाली राष्ट्रीय स्थिरीकरण रणनीति के कार्यान्वयन का समर्थन करना;

(ड) सोमाली परिवर्तन योजना प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए प्रासंगिक सोमाली मंत्रालयों और संस्थानों का समर्थन करें और एटीएमआईएस के उद्देश्यों को साकार करने में आवश्यक सहायता प्रदान करना;

25. यह पुष्टि करता है कि जहां संकल्प 2607 (2021) "एमीसोम" को संदर्भित करता है, उसे एटीएमआईएस के संदर्भ में पढ़ा जाएगा;

26. अफ्रीकी संघ के सदस्य राज्यों को 31 दिसंबर 2022 तक पांच गठित पुलिस इकाइयों सहित न्यूनतम 1040 पुलिस कर्मियों सहित, 19,626 वर्दीधारी कर्मियों को तैनात करने के लिए अधिकृत करता है और इस तारीख तक 2000 कर्मियों को वापस लेने के अफ्रीकी संघ शांति और सुरक्षा परिषद के निर्णय का समर्थन करता है;

27. 1 जनवरी 2023 और 31 मार्च 2023 के बीच अफ्रीकी संघ के सदस्य राज्यों को 17,626 वर्दीधारी कर्मियों को तैनात करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें पांच गठित पुलिस इकाइयों सहित न्यूनतम 1040 पुलिस कर्मी शामिल हैं;

28. यह नोट करता है कि संयुक्त प्रस्ताव और सीओएनओपी में 14,626 वर्दीधारी कर्मियों को और कम करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें चरण 2 (सितंबर 2023) के अंत तक 1040 पुलिस की न्यूनतम संख्या शामिल है, चरण 3 (जून 2024) के अंत तक, 1040 पुलिस कर्मियों की न्यूनतम संख्या सहित 10,626 वर्दीधारी कर्मी शामिल है, और, चरण 4 के अंत तक (दिसंबर 2024) शून्य कर्मी शामिल है और सोमालिया की स्थिति और इस संकल्प के अनुच्छेद 51 में उल्लिखित नियमित, संयुक्त तकनीकी आकलन, इन कटौती को ध्यान में रखते हुए अधिकृत करने का अपना इरादा व्यक्त करता है;

29. अफ्रीकी संघ से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है कि निम्नलिखित के लिए संरचनाएं उपलब्ध हैं:

(क) एटीएमआईएस की स्पष्ट निगरानी, और मिशन एवं उसके दलों के लिए जवाबदेही तंत्र;

(ख) मिशन की स्पष्ट कमान और नियंत्रण और इसके दल के बीच परिचालन समन्वय;

(ग) फोर्स कमांडर और सेक्टर कमांडरों के अधीन समन्वित परिचालन निर्णयन;

(घ) हवाई संपत्ति सहित मिशन को सक्षम करने वाली इकाइयों की कमान, नियंत्रण और जवाबदेही;

(ङ) एटीएमआईएस क्षेत्रों में मोबाइल बलों का निर्माण और तैनाती; तथा

(च) एटीएमआईएस निर्देश राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने तथा नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए हैं;

30. अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के साथ, यूनिट आवश्यकताओं के विवरण (*एसयूआर*) को ध्यान में रखते हुए, और मौजूदा संसाधनों के भीतर, एटीएमआईएस की परिचालन क्षमताओं की निरंतर समीक्षा करने का आग्रह करता है:

(क) अनिवार्य कार्यों को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल बढ़ाने; और

(ख) संसाधन आवश्यकताओं में अंतर की पहचान और स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से संसाधनों तथा उपकरणों की आपूर्ति के लिए विशिष्ट अनुरोध करना;

31. सोमाली सुरक्षा और पुलिस बलों के साथ संयुक्त या समन्वित संचालन के संदर्भ में ऑपरेशनों के प्रारंभिक संचालन और समीक्षा चरणों में यूएनएसओएम और एचआरडीडीपी को लागू करने में यूएनएसओएस के साथ एटीएमआईएस बलों के सहयोग को जारी रखने के महत्व पर जोर देता है।

32. अफ्रीकी संघ, *एटीएमआईएस* बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन एवं इन आरोपों की नियमित निगरानी तथा त्वरित और गहन जांच एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ पारदर्शिता, आचरण और अनुशासन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने तथा जहां उपयुक्त हो, यूएनएसओएम के साथ इन प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य बनाने के लिए एटीएमआईएस से उत्तरदायित्व लेने का आह्वान करता है तथा अफ्रीकी संघ के साथ सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों से उनके सहयोग को मजबूत करने तथा एटीएमआईएस के अनुपालन और उत्तरदायी साधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता है।

33. *एटीएमआईएस* से यह अनुरोध करता है कि सीसीटीएआरसी के साथ सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करे और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि संयुक्त राष्ट्र सहित सभी प्रासंगिक सदस्यों के साथ सूचना प्रदान की जाए, जो एटीएमआईएस की रिपोर्टिंग में एकीकृत किया गया है एवं परिचालित दिशानिर्देशों और योजनाओं में दर्शाया गया है तथा मानवतावादी मानवाधिकारों और संरक्षक सदस्यों के सहयोग से सेना तथा पुलिस योगदानकर्ताओं के पूर्ण समर्थन का अनुरोध करता है।

34. एटीएमआईएस से यह अनुरोध करता है कि संघर्ष में यौन उत्पीड़न को रोकने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए संयुक्त विज्ञप्ति और राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करे तथा सभी एटीएमआईएस घटकों की गतिविधियों में इन विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघर्ष में यौन हिंसा के खतरे के मामलों में आंकड़ा संग्रह, खतरे का विश्लेषण और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है तथा यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार पर शून्य-सहनशीलता नीति की *पुष्टि की जाती* है, इस तरह के शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, अफ्रीकी संघ और सेना तथा पुलिस-योगदानकर्ता देशों से कार्मिकों की स्क्रीनिंग करने, जोखिम मूल्यांकन करने, सभी कार्मिकों को प्रासंगिक प्रशिक्षण देने, दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़ितों को राहत पहुँचाने, देखभाल करने तथा सुरक्षा एवं समर्थन करने, आरोपों की समय पर जांच करने, अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने और उन इकाइयों को प्रत्यावर्तित करने के लिए अनुरोध करता है, जहां सदस्यों द्वारा व्यापक अथवा नियमित यौन शोषण या दुर्व्यवहार के विश्वसनीय सबूत पाए गए हैं और इस संबंध में अफ्रीकी संघ से संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने का *अनुरोध करता है*

35. सेना और पुलिस योगदानकर्ता देशों द्वारा एटीएमआईएस में महिला वर्दीधारी कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है और एटीएमआईएस से उसके अभियानों में महिलाओं की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने जनादेश जारी करते समय समान स्त्री-पुरुष दृष्टिकोण को समाहित करने का *आग्रह करता है;*

36. अफ्रीकी संघ से एटीएमआईएस नागरिक कार्मिक पदों पर सोमाली नागरिकों की भर्ती के लिए सोमालिया के अनुरोध को संज्ञान में लेता है।

<u>सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यालय</u> (यूएनएसओएस)

37. महासचिव से संभार तंत्र सहायता पैकेज प्रदान करना जारी रखने और अफ्रीकी संघ एवं एफजीएस के परामर्श से, एचआरडीडीपी के पूर्ण अनुपालन में, यूएनएसओएम के लिए यूएनएसओएस के माध्यम से, इस संकल्प के अनुच्छेद 26 और 27 के अनुरूप एटीएमआईएस वर्दीधारी कर्मियों के आधार पर, एक उपयुक्त संभार तंत्र सहायता योजना विकसित करने का अनुरोध करता है। संकल्प 2245 (2015) के अनुच्छेद 2 में 1 जनवरी, 2023 से 70 एटीएमआईएस नागरिकों से 85 एटीएमआईएस नागरिकों तक बढ़ाने, एटीएमआईएस के सैन्य और पुलिस कार्यों का समर्थन करने तथा संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और एफजीएस के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट कोष के माध्यम से सोमालिया में 13,900 सोमाली सुरक्षा बलों का समर्थन करता है जिनमें राज्य और संघीय पुलिस का यथोचित हिस्सा शामिल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना की तरह औपचारिक रूप से सोमाली सुरक्षा बलों में एकीकृत हैं और एटीएमआईएस, जो एसटीपी का सीधा कार्यान्वयन करता है, के साथ संयुक्त या समन्वित अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

38. अनुच्छेद 37 में निर्धारित यूएनएसओएस के माध्यम से समर्थन के लिए उपयुक्त सोमाली सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने पर विचार करता है जो अनुच्छेद 7 और 8 में निर्धारित बल एकीकरण और उत्पादन में प्रगति तथा इस संकल्प के अनुच्छेद 26 और 27 में निर्धारित एटीएमआईएस वर्दीधारी कार्मिकों की संख्या में कमी करने के अधीन है;

39. संभार तंत्र सहायता के वितरण के साथ-साथ अन्य वितरण वस्तुओं जैसे सैन्य अभियानों की योजना बनाने के लिए यूएनएसओएस को एकीकृत करना, काफिले और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नागरिकों की सुरक्षा और मुख्य आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा सहित यूएनएसओएस के साथ एटीएमआईएस और सोमाली सुरक्षा बलों के संयुक्त रूप से कार्य करने के महत्व पर जोर देता है।

40. इस बात पर जोर देता है कि संयुक्त राष्ट्र के संचालन सहायता विभाग की पर्यावरण रणनीति (द्वितीय चरण) के कार्यान्वयन से शांति बनाए रखने और सुरक्षा समर्थन की स्थिति में सुधार किया गया है जो संसाधनों के अच्छे प्रबंधन और मिशन की सकारात्मक विरासत पर बल देता है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिशनों में विस्तारित नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लक्ष्य की पहचान करता है। यूएनएससीएपी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक क्षेत्र संचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से स्थानांतरित करने के लिए महासचिव के आह्वान को ध्यान में रखते हुए लागत कम करने, दक्षता प्रदान करने और मिशन को लाभान्वित करने पर जोर देता है।

41. तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) के खतरे का मुकाबला करने के लिए सोमाली सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, उपकरण और परामर्श के लिए महासचिव से संयुक्त राष्ट्र का समर्थन जारी रखने का अनुरोध करता है।

42. संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और सोमालिया के बीच विशेष रूप से एचआरडीडीपी के अनुपालन में भागीदारी की आधारशिला निगरानी और जवाबदेही होनी चाहिए। महासचिव से यह सुनिश्चित करने का *अनुरोध करता है कि गैर-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल को कोई भी सहायता* एचआरडीडीपी के सख्त अनुपालन में प्रदान की जाए और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र समर्थन के प्रावधान की शर्तों पर संयुक्त राष्ट्र के साथ अद्यतन समझौता ज्ञापन पर सोमालिया और अफ्रीकी संघ से सहमत होने का अनुरोध करता है।

43. महासचिव *ने* अफ्रीकी संघ को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अधिदेश के अनुरूप एटीएमआईएस की योजना, परिनियोजन और रणनीतिक प्रबंधन पर तकनीकी और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के साथ-साथ इस संकल्प के कार्यान्वयन का समर्थन करने में अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

44. पिछले 15 वर्षों में यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान की जा रही निरंतर वित्तीय सहायता का *स्वागत करता है* सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन, विशेष रूप से, एटीएमआईएस के रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्तीय भागीदारों को शामिल

करने के महत्व पर जोर देता है तथा वित्तीय और भौतिक सहायता के लिए कड़ी निगरानी और जवाबदेही के महत्व पर जोर देता है;

45. तकनीकी सहायता तथा सीसीटीएआरसी के प्रभावी कामकाज और संशोधनों के संवितरण का समर्थन करने के लिए साथ ही साथ सेना एवं पुलिस वजीफा, उपकरण और नए दाताओं सहित सदस्य राज्यों से *एटीएमआईएस* के लिए अनुमानित, टिकाऊ और बहु-वर्षीय समर्थन प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह करता है, जिसमें एटीएमआईएस के नागरिक घटक के लिए अफ्रीकी संघ को अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है ताकि एसटीपी, एनएसए और व्यापक स्थिरीकरण प्रयास के कार्यान्वयन के लिए इसके समर्थन को सक्षम बनाया जा सके।

46. सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट कोष को धन उपलब्ध कराने पर विचार करने का *आग्रह करता है।* जिसमें सोमाली सुरक्षा और पुलिस बलों के प्रशिक्षण, उपकरण और सलाह के लिए धन शामिल है। आईईडी के खतरे का मुकाबला करना एवं छोटे और हल्के हथियारों के अवैध प्रसार में शीर्ष पर लाने तथा एटीएमआईएस के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों को जुटाने में अफ्रीकी संघ का समर्थन पाना है, जिसमें वित्तीय योगदान के माध्यम से संसाधन जरूरतों के अंतराल को निर्धारित करने तथा संसाधनों और उपकरणों के लिए विशिष्ट अनुरोध शामिल है;

47. संकल्प 2246 (2015) के अनुरूप समुद्री पुलिस बल के लिए क्षमता निर्माण के साथ-साथ सदस्य राज्यों से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करने का *आग्रह करता है, ताकि* राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय संस्थान एक एकीकृत सोमाली सुरक्षा क्षेत्र विकसित कर सकें।

48. सोमालिया और उसके भागीदारों को एक समन्वित कदम उठाने की आवश्यकता पर बल *देता है* सोमालिया के नेतृत्व वाले राजनीतिक और सुरक्षा सुधारों का समर्थन करते हुए स्थिरता सुनिश्चित करने, अधिकतम प्रभाव डालने और सोमालिया की सुरक्षा जिम्मेदारी के परिवर्तन को प्रगतिशील एवं सक्षम बनाए रखने के लिए:

(क) एफजीएस से सोमाली संक्रमण योजना सामरिक संचालन समिति, सुरक्षा और न्याय समिति तथा सोमालिया विकास और पुनर्निर्माण सुविधा समिति की नियमित उच्च-स्तरीय बैठकों के माध्यम से रणनीतिक समन्वय का नेतृत्व करने का *आग्रह करता है।*

(ख) एफजीएस से *एटीएमआईएस* और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय में एफएमएस के साथ सोमाली सुरक्षा बल निर्माण सहित सभी संयुक्त या समन्वित संचालन, और रणनीतिक और परिचालन निर्णयों पर सहमत होने का आग्रह करता है;

(ग) एफजीएस, एफएमएस, एटीएमआईएस, यूएनएसओएम, यूएनएसओएस तथा संयुक्त राष्ट्र के देशों के समूह और सोमालिया के अन्य बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय भागीदारों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए तकनीकी साझेदारी समन्वय कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एफजीएस, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र संघ से *अनुरोध करता है*:

(i) प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के क्षेत्र-दर-क्षेत्र डैशबोर्ड के निर्माण सहित जानकारी साझा करना;

(ii) विश्लेषण, योजना और प्रदर्शन मूल्यांकन करना;

(iii) क्षमता निर्माण सहायता, प्रशिक्षण, देखरेख के द्विपक्षीय प्रावधान का समन्वय करना, सोमाली सुरक्षा और पुलिस बलों को उपकरण और आपूर्तियाँ प्रदान करना;

(iv) यह सुनिश्चित करना कि इस तरह की सहायता और सहायता प्रासंगिक के अनुरूप प्रदान की जाती है संकल्प 2607 (2021) के प्रावधान; तथा

(v) यह सुनिश्चित करना कि यह समर्थन और सहायता एचआरडीडीपी के अनुरूप है;

49. सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत और चार्टर के VIII अध्याय के अनुरूप सुरक्षा परिषद के अधिकार के अधीन अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाले शांति समर्थन कार्यों के लिए पूर्वानुमेयता, स्थिरता और वित्तीय लचीलापन बढ़ाने की आवश्यकता *पर जोर देता है* और संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों के लिए उपलब्ध विकल्पों की पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए और स्वैच्छिक वित्त पोषण की सीमाओं पर विचार करते हुए एटीएमआईएस के सुरक्षित भविष्य के लिए वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए महासचिव, अफ्रीकी संघ तथा सदस्य राज्यों से एटीएमआईएस के लिए अग्रिम धनराशि व्यवस्था खोजने के प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मूल्यांकन और रिपोर्टिंग

50. संयुक्त राष्ट्र *अफ्रीकी संघ, एफजीएस,* यूरोपीय संघ तथा अन्य दाताओं सहित संयुक्त रूप से एक समावेशी, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रासंगिक, स्पष्ट और यथार्थवादी बेंचमार्क की पहचान करने के लिए अनुरोध करता है, जिसमें सुरक्षा परिवर्तन के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तथा आकलन योग्य संकेतक शामिल हैं और सुरक्षा परिवर्तन के कार्यान्वयन का आकलन करने,अफ्रीकी संघ द्वारा प्रस्तावित एटीएमआईएस की प्रभावशीलता के लिए बेंचमार्क और 30 सितंबर 2022 तक के 2594 (2021) संकल्प को ध्यान में रखते हुए एफजीएस द्वारा प्रस्तावित एसटीपी और एनएसए के कार्यान्वयन के लिए बेंचमार्क शामिल हैं, जो आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को ध्यान में रखते हैं।

51. *अफ्रीकी यूनियन एफजीएस,* यूरोपीय संघ और अन्य दाताओं के साथ *संयुक्त रूप से* की गई प्रगति की नियमित, संयुक्त तकनीकी मूल्यांकन करने, और इस संकल्प के अनुच्छेद 50 में अनुरोध किए गए मापदंडों के अनुरूप एटीएमआईएस में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने के अगले कदमों के विषय में आगे के निर्णय लेने हेतु सुरक्षा परिषद का मार्गदर्शन और यूएनएसओएस द्वारा उपलब्ध कराए गए समर्थन तथा इस विषय में सुरक्षा परिषद को 15 फरवरी 2023 तक रिपोर्ट करने का *अनुरोध करता है;*

52. एफजीएस से सुरक्षा परिषद को क्रमशः 10 जुलाई 2022, 10 अक्टूबर 2022 और 10 जनवरी 2023 तक अद्यतन सूचना प्रदान करने का *अनुरोध करता है*:

(क) इस संकल्प के पैरा 7 और 8 में निर्धारित एसटीपी और एनएसए और बल उत्पादन और एकीकरण को लागू करने में हुई प्रगति;

(ख) 27 मई 2021 को स्वीकृत रोडमैप को लागू करने में प्रगति;

53. एटीएमआईएस के आदेश पत्र के कार्यान्वयन पर महासचिव के माध्यम से 10 जुलाई 2022, 10 अक्टूबर 2022 और 10 जनवरी 2023 तक सुरक्षा परिषद को सूचित करते रहने के लिए अफ्रीकी संघ से *अनुरोध करता है और* इस संबंध में यह भी अनुरोध करता है कि इन रिपोर्टों में निम्नलिखित विशिष्ट रिपोर्टिंग शामिल हों:

(क) एफजीएस के साथ समन्वय तंत्र के उपयोग और प्रभावशीलता सहित एसटीपी और एनएसए के समर्थन में संयुक्त संचालन पर प्रगति;

(ख) एटीएमआईएस के आदेश और नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन;

(ग) पैरा 23 में उल्लिखित रणनीतिक उद्देश्यों में हुई प्रगति;

(घ) संयुक्त प्रस्ताव और सीओएनओपी में उल्लिखित कार्यों में हुई प्रगति का मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन;

(ङ) आदेश और नियंत्रण तथा आचरण एवं अनुशासन सहित पूर्व चिह्नित न्यून निष्पादन को संबोधित के समाधान के लिए जवाबदेही निर्धारित करने संबंधी उपाय;

(च) नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभावशीलता;

(छ) उपकरण समीक्षा परिणाम और बल संपत्ति का उपयोग;

54. महासचिव से संकल्प 2592 (2021) के पैरा 17 में उनके द्वारा मांगे गए नियमित रिपोर्टों में इस संकल्प के कार्यान्वयन के बारे में सुरक्षा परिषद को सूचित करते रहने का अनुरोध करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संकल्प 2592 (2021) के पैरा *18 में उल्लिखित* यूएनएसओएम की रणनीतिक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए महासचिव के अनुरोध को दुहराता *है तथा सोमालिया में वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के समापन के बाद इसके पूरा होने की एक नई तारीख प्रदान करने की इच्छा व्यक्त करता है।*

55. इस मामले में सक्रिय रूप से सुविज्ञ रहने का निर्णय करती *है।*

[फा. सं. यू. II/152/01/2016]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र में संख्यांक का. आ. 2220 (अ), तारीख 28 जून, 2016 के अधीन प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार आदेश क्रम संख्यांक का. आ. 1797 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 30th November, 2022

S.O. 5556(E).— In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Somalia and Eritrea Order, 2016, namely :-

(1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Somalia and Eritrea (Second Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Somalia and Eritrea Order, 2016, (hereinafter referred to as the said Order), in the preamble, for the word, figures and brackets "and 2244 (2015)", the figures, brackets and word "2244 (2015), 2607 (2021) and 2628 (2022)" shall be substituted.

3. In paragraph 2 of the said Order, in sub-paragraph (1), in clause (a), for the word, figures and brackets "and 2244 (2015)", the figures, brackets and word "2244 (2015), 2607 (2021) and 2628 (2022)" shall be substituted.

4. In paragraph 4 of the said Order, under the heading "I. Arms Embargo" in clause (c), in the proviso,-

(a) in item (ii), after the brackets, words and figures "{reference paragraph 10 (a) of resolution 2111 (2013)}", the following shall be inserted namely:-

"and Annex A and Annex B of resolution 2607 (2021) [reference paragraphs 24-25 of resolution 2607 (2021)]".

(b) in item (iii), after sub-item (d), the following sub–items shall be inserted, namely:-

"(e) African Union Mission in Somalia (AMISOM) shall be substituted by the African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS) [paragraphs 22 and 25 of Resolution 2628(2022)];

(f) Somali Security Sector Institutions other than those of the FGS (SSSI);"

(c) after item (vii), the following items shall be inserted, namely:-

"(viii) Entry into Somali ports for temporary visits of vessels carrying weapons and military equipment for defensive purposes provided that such items remain at all times aboard such vessels [Paragraph 34(d) of Resolution 2607];

(ix) deliveries of weapons and military equipment, or the provision of technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities, intended solely for the development of:

(i) the Somali National Security Force of FGA (SNSF), to provide security for the Somali people, except in relation to items in Annexes A and B to the resolution 2607, which are subject to prior approval of the Committee on case-by-case basis and advance notification for information to the Committee, respectively. in paragraphs 21(a), 23 and 24 of Resolution 2607];

(ii) the Somali Security Sector Institutions other than those of the FGS (SSSIs), to provide security for the Somali people, except in relation to items in Annexes A and B to Resolution 2607, which are subject to the applicable approvals and notification procedures [as set out in paragraphs 21(b)&(c), 25 and 26 of Resolution 2607].

5. After Annexure 5 of the said Order, the following Annexures shall be inserted namely –

ANNEXURE 6

Resolution 2607 (2021)

Adopted by the Security Council at its 8905 meeting, on 15 November 2021

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions and statements of its President on the situation in Somalia,

Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia, and *underscoring* the importance of working to prevent destabilising effects of regional disputes from spilling over into Somalia,

Welcoming the agreements reached between the Federal Government of Somalia (FGS) and Somalia's Federal Member States (FMS) on 17 September 2020 and 27 May 2021, *urging* the FGS and FMS to implement these agreements and conduct peaceful, credible and inclusive elections in 2021,

Believing that sustained progress in state-building in Somalia will prevent terrorist groups, including Al-Shabaab from exploiting the situation in Somalia, *expressing concern* about continued delays in consolidating Somalia's federal system, underscoring the importance of progress on national priorities, including the National Security Architecture, the Somalia Transition Plan (2021) (STP), the ninth National Development Plan and the jointly-agreed Mutual Accountability Framework, and reaching agreement on a federated police and justice system, fiscal federalism, power - and resource-sharing, and the constitutional review, in this regard *welcoming* the roadmap agreed on 27 May 2021, and urging the FGS and the FMS to implement it without delay,

Encouraging the FGS to coordinate with international and regional partners regarding its needs in developing its National Security Forces, *noting* that these forces require access to weapons and specialist equipment, in accordance with the measures in this resolution, in order to perform their functions effectively,

Welcoming progress made by the FGS on weapons and ammunition management (WAM), including the adoption of the National WAM Strategy, *urging* continued work codifying and implementing weapons and ammunition management policies including developing an accountable weapons distribution and tracing system for all Somali security forces, *recognising* that effective weapons and ammunition management is the responsibility of the FGS and FMS, and *encouraging* Somalia's partners to support the FGS and FMS with this, and in line with Somalia's National Security Architecture and the STP,

Condemning the supply of weapons and ammunition to and through Somalia in violation of the arms embargo, especially when they reach Al-Shabaab and affiliates linked to ISIL, and when they undermine the sovereignty and territorial integrity of Somalia, as a serious threat to peace and stability in the region, and *further condemning* continued illegal supply of weapons, ammunition and IED components from Yemen to Somalia,

Condemning Al-Shabaab's terrorist attacks in Somalia and beyond, *expressing* grave concern that Al-Shabaab continues to pose a serious threat to the peace, security and stability of Somalia and the region, particularly through its increased use of improvised explosive devices (IEDs) and exploitation of the licit financial system, and *further expressing* grave concern at the continued presence in Somalia of affiliates linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL also known as Da'esh),

Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and international law, including applicable international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law,

threats to international peace and security caused by terrorist acts,

Recognising that the threat posed by Al-Shabaab to peace, security and stability in Somalia and the region goes beyond the group's conventional military action and asymmetric warfare, *expressing serious concern* at Al-Shaabab's ability to generate revenue as documented in the final report of the Panel of Experts (the Panel) on Somalia (S/2021/849) *welcoming* the FGS' efforts to strengthen the Somali Financial Sector to identify and monitor money laundering risks and combat terrorist financing, noting the steps set out by the FGS in the STP on institutional capacity building, which seek to develop these capabilities, noting the importance of financial services in enabling Somalia's economic future, *further welcoming* efforts by the FGS, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the Panel to develop a plan to disrupt Al-Shabaab finances, and urging engagement from the FGS, FMS, Somali financial institutions, the private sector and the international community to support this process,

Expressing concern at the continued reports of corruption and diversion of public resources in Somalia, *welcoming* efforts made by the FGS to reduce corruption including the enactment of the Anti-Corruption Law on 21 September 2019 and the establishment of the Anti-Corruption Commission, as well as the ratification of the United Nations Convention Against Corruption, welcoming progress made by the FGS and FMS in strengthening public financial management and the positive work of the Financial Reporting Centre, and calling for the FGS and FMS to continue efforts to address corruption, and to continue to accelerate the pace of reform,

Welcoming measures taken by the FGS, FMS and United Nations Member States with charcoal destination markets to reduce the export of charcoal, *urging* monitoring and control of existing charcoal stockpiles at export points, *encouraging* further development of Somalia's National Policy on Charcoal, which aims to develop the sustainable management of domestic charcoal use, to address disposal of stockpiles,

Expressing concern at the reported ability of Al-Shabaab to exploit the trade in sugar and urging the FGS, FMS and regional stakeholders to address this,

Expressing concern at continued reports of illegal and unregulated fishing in waters where Somalia has jurisdiction, noting the link between illegal fishing and Al-Shabaab's ability to generate revenue, *encouraging* the Somali authorities, with support from the international community, to ensure fishing licenses are issued in accordance with the appropriate Somali legislation, *further encouraging* the FGS, FMS and Somali authorities to work with the UNODC, their international partners and other stakeholders to improve maritime domain awareness and enforcement capabilities,

Expressing concern at the situation in Galmadug, *reiterating* the importance of peaceful dispute resolution both in the run-up to elections in 2021 and beyond, and reaffirming the importance of inclusive politics, and democratic elections in ensuring long-term peace and stability in Somalia,

Expressing serious concern at the humanitarian situation in Somalia, noting the combined threat posed by flooding, drought, locust infestation, forced displacement, and COVID-19, and *condemning in the strongest terms* any party obstructing the safe delivery of humanitarian assistance, any misappropriation or diversion of any humanitarian funds or supplies, and acts of violence against or harassment of humanitarian workers,

Noting with concern reports, including from the Secretary-General, which document worrying levels of sexual and gender-based violence in Somalia, *further noting* with concern that Somalia remains one of the deadliest conflict areas for children, as outlined in the 2021 Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict, *further noting* with concern the high levels of recruitment of children in armed conflict in violation of international law and high levels of abductions, with Al-Shabaab continuing to be the main perpetrator, and urging the Somali authorities to further strengthen efforts to address these "six grave violations" against children as identified by the Secretary-General, including by implementing measures in line with resolution 2467 (2019),

Reiterating the importance of inclusive dialogue and local reconciliation processes for stability in Somalia, *reaffirming* the importance of both the FGS and FMS engaging in constructive dialogue to de-escalate tensions between them, and further reiterating that the successful and peaceful conduct of elections in 2021 as planned and agreed can enable Somalia to refocus on addressing pressing problems, including among other things, the threat posed by Al-Shabaab, trafficking of weapons and ammunition, humanitarian needs, floods, drought, and COVID-19 and enable all parties to advance Somalia's national priorities,

Taking note of the final report of the Panel, *welcoming* the increased cooperation between the Panel and the FGS, and recalling that panels of experts operate pursuant to mandates from the Security Council,

Expressing support for the FGS in its efforts to reconstruct the country, counter the threat of terrorism, and stop the trafficking of weapons and ammunition, *further expressing* its intention to ensure the measures in this resolution will enable the FGS in the realisation of these objectives, *noting* that the security situation in Somalia continues to necessitate these measures, including strict controls on the movement of arms but affirming that it shall keep the situation in Somalia under constant review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including any modification, possible benchmarks, suspension or lifting of the measures, as may be needed in light of the progress achieved and compliance with this resolution,

Recalling paragraphs 1 to 8 of resolution 2444 (2018), *reaffirming* that it will continue to follow developments towards the normalisation of relations between Eritrea and Djibouti and will support the two countries in the resolution of these matters in good faith,

Underscores its objective in this resolution is to support state- and peace- building in Somalia including by reducing the threat to peace and security posed by Al-Shabaab and by reducing the destabilising impact of Al-Shabaab's activities, in Somalia and the region, and by supporting Somalia with security sector reforms, especially weapons and ammunition management, and through the measures and mechanisms outlined in the following operative paragraphs,

Determining that the situation in Somalia continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

Part 1: Degrading Al-Shabaab

1. *Reiterates* that Al-Shabaab poses a threat to peace and security, and that its terrorist and other activities have a destabilising impact in Somalia and the region, and underscores the need to target Al-Shabaab's finances, improve maritime domain awareness, prevent illicit revenue generation, including from the sale of charcoal, and reduce the threat posed by IEDs;

1a: Targeting illicit finances

2. *Notes with concern* Al-Shabaab's ability to generate revenue and launder, store and transfer resources, *calls upon* the FGS to continue working with Somali financial authorities, private sector financial institutions and the international community to identify, assess and mitigate money laundering and terrorist financing risks, improve compliance (including enhanced Know Your Customer and due diligence procedures) and strengthen supervision and enforcement, including through increased reporting to the Central Bank of Somalia and Financial Reporting Centre in line with the Anti-Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism Act (2016) as well as the Mobile Money Regulations (2019), *commends* the FGS for signing a National Identification (ID) bill and *encourages* the development of a unique Somali ID as a matter of priority to improve financial access and compliance and counter the financing of terrorism, *further encourages* support from the international community in addressing these risks and requests the FGS, UNODC and the Panel to continue exchanging information about Al-Shabaab's finances and to continue working with stakeholders to develop a plan to disrupt Al -Shabaab's finances and exploitation of the licit financial system;

3. *Requests* the FGS to strengthen cooperation and coordination with other United Nations Member States, particularly other Member States in the region, and with international partners to prevent and counter the financing of terrorism, including compliance with resolution 1373 (2001), resolution 2178 (2014), resolution 2462 (2019), and relevant domestic and international law, and requests the FGS to submit, in its regular reporting to the Council, an update on specific actions taken by the Somali authorities to counter the financing of terrorism;

1b: Maritime Interdiction and improving maritime domain awareness

4. Encourages the UNODC, within its current mandate, under the Indian Ocean Forum on Maritime Crime, to bring together relevant States and international organisations, including European Naval Force Operation Atalanta, Combined Maritime Forces (CMF) and other naval forces in the region to enhance regional cooperation on responding to illicit maritime flows and disrupt all forms of trafficking in licit and illicit goods that may finance terrorist activities in Somalia, and support the FGS and FMS to improve their maritime domain awareness and enforcement, including in relation to the role of fishing vessels in trafficking and illicit trade;

5. *Decides* to renew and expand the provisions set out in paragraph 15 of resolution 2182 (2014) until 15 November 2022 and *authorises* Member States, acting nationally or through voluntary multinational naval partnerships such as "Combined Maritime Forces," in cooperation with the FGS and which the FGS has notified to the Secretary-General and which the Secretary-General has subsequently notified to all Member States, in order to ensure strict implementation of the arms embargo on Somalia, the charcoal ban, and the IED components ban, to inspect, without undue delay, in Somali territorial waters and on the high seas off the coast of Somalia extending to and including the Arabian sea and Persian Gulf, vessels bound to or from Somalia which they have reasonable grounds to believe are:

(i) carrying charcoal from Somalia in violation of the charcoal ban;

(ii) carrying weapons or military equipment to Somalia, directly or indirectly, in violation of the arms embargo on Somalia;

(iii) carrying weapons or military equipment to individuals or entities designated by the Committee pursuant to resolution 751 (1992); or

(iv) carrying IED components identified in Part I of Annex C to this resolution in violation of the IED components ban;

1c: Somalia Charcoal ban

6. *Condemns* any exports of charcoal from Somalia in violation of the total ban on the export of charcoal, *reaffirms* its decision regarding the ban on the import and export of Somali charcoal, as set out in paragraph 22 of its resolution 2036 (2012) ("the charcoal ban"), and paragraphs 11 to 21 of resolution 2182 (2014);

7. *Welcomes* measures taken by the FGS, FMS and Member States to reduce the export of charcoal from Somalia, *reiterates* its requests that the African Union Mission in Somalia (AMISOM) support and assist the FGS and FMSs in implementing the total ban on the export of charcoal from Somalia, encourages further development of Somalia's National Policy on Charcoal to develop the sustainable management of domestic charcoal use, encourages the Food and Agriculture Organization (FAO) to provide the FGS with data and enhanced analysis on domestic charcoal production to inform the development of the FGS National Policy on Charcoal and calls upon AMISOM to facilitate regular access for the Panel to charcoal exporting ports;

8. *Reaffirms* the importance of the efforts of the UNODC and its international partners to monitor and disrupt the export and import of charcoal to and from Somalia;

1d: IED components restrictions

9. *Noting* the increase in IED attacks undertaken by Al-Shabaab, *decides* that all States shall prevent the direct or indirect sale, supply or transfer of the items in part I of Annex C to this resolution to Somalia from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft if there is sufficient evidence to demonstrate that the item(s) will be used, or a significant risk they may be used, in the manufacture in Somalia of improvised explosive devices;

10. *Further decides* that, where an item in part I of Annex C to this resolution is directly or indirectly sold, supplied or transferred to Somalia consistent with paragraph 9, the State shall notify the Committee of the sale, supply or transfer no more than 15 working days after the sale, supply or transfer takes place, and stresses the importance that notifications pursuant to this paragraph contain all relevant information, including the purpose of the use of the item(s), the end user, the technical specifications and the quantity of the item(s) to be shipped;

11. *Calls upon* Member States to undertake appropriate measures to promote the exercise of vigilance by their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction that are involved in the sale, supply, or transfer of explosive precursors and materials to Somalia that may be used in the manufacture of improvised explosive devices, including inter alia items in part II of Annex C, to keep records of transactions and share information with the FGS, the Committee and the Panel regarding suspicious purchases of or enquiries into these chemicals by individuals in Somalia and to ensure that the FGS and FMS are provided with adequate financial and technical assistance to establish appropriate safeguards for the storage and distribution of materials;

12. *Encourages* international and regional partners of Somalia to implement continued specialist training of FGS Explosive Ordnance Disposal teams and to provide appropriate equipment and coordinate support to reinforce Somali capacity in the analysis of explosives;

Part 2: supporting state- and peace-building in Somalia

2a: Security sector reform and compliance with international law

13. *Calls upon* the FGS, in coordination with the FMS, to accelerate the implementation of the National Security Architecture and STP, and urges the FGS and FMS to implement the 27 May 2021 roadmap;

14. *Further calls upon* the FGS and FMS to enhance civilian oversight of their security apparatus, to continue to adopt and implement appropriate vetting procedures of all defence and security personnel, including human rights vetting, and to investigate and, as appropriate, prosecute individuals responsible for violations of international law, including international humanitarian law and human rights law, and sexual and gender-based violence in conflict and post-conflict situations, and in this context recalls the importance of the Secretary-General's Human Rights and Due Diligence Policy in relation to the support provided by the United Nations to Somali security forces and AMISOM;

15. *Calls upon* the international community to support implementation of the STP to help develop credible, professional and representative Somali security forces;

16. *Calls upon* all parties to the conflict in Somalia to comply with international humanitarian law, and urges them to continue conducting prompt and full investigations when reports of civilian casualties resulting from military operations arise;

2b: Weapons and ammunition management and preventing illegal movement of weapons to and within Somalia

17. *Welcomes* progress on weapons and ammunition management and underlines the responsibility of the FGS and FMS to ensure the safe and effective management, storage and security of their stockpiles of weapons, ammunition and other military equipment and their distribution, including implementation of a system which allows tracking of all such military equipment and supplies to the unit level;

18. *Reaffirms* that the FGS, in cooperation with the FMS and AMISOM, shall document and register all weapons and military equipment captured as part of offensive operations or in the course of carrying out their mandates, including recording the type and serial number of the weapon and/or ammunition, photographing all items and relevant markings and facilitating inspection by the Panel of all military items before their redistribution or destruction;

19. *Calls upon* the international community to provide additional and coordinated support to continue to develop the weapons and ammunition management capacity of the FGS and FMS, with a particular focus on training, storage, support for infrastructure and distribution, technical assistance and capacity building and *encourages* international and regional partners to coordinate their efforts to support the strengthening of FGS bodies in charge of implementing the requirements of this resolution;

20. *Emphasises* that effective weapons and ammunition management will reduce the ability of Al-Shabaab and other armed groups to obtain weapons and reduce the threat to peace and security posed by them, in Somalia and the region, and reaffirms that all States shall, for the purposes of establishing peace and stability in Somalia, implement a general and complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Somalia, including prohibiting the financing of all acquisitions and deliveries of weapons and military equipment and the direct or indirect supply of technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities, until the Council decides otherwise (as initially imposed by paragraph 5 of its resolution 733 (1992) and paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002), hereafter "the arms embargo";

21. *Recognises* that Somali National Security Forces (SNSF) and Somali Security Sector Institutions other than those of the FGS (SSSIs) will require access to weapons and specialist equipment, in line with Somalia's National Security Architecture and the STP, in order to perform their functions effectively and *reaffirms* that the arms embargo shall not apply to:

(a) deliveries of weapons and military equipment, or the provision of technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities, intended solely for the development of the SNSF, to provide security for the Somali people, except in relation to items in Annexes A and B to this resolution, which are subject to the applicable approvals and notification procedures as set out in paragraphs 23 and 24 to this resolution;

(b) to deliveries of weapons and military equipment, intended solely for the development of SSSIs, to provide security

for the Somali people, except in relation to items in Annexes A and B to this resolution, which are subject to the applicable approvals and notification procedures as set out in paragraphs 25 and 26 below;

(c) the provision of technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities, intended solely for the development of SSSIs, to provide security for the Somali people, which are also subject to the applicable approvals and notification procedures as set out in paragraph 26 below;

22. *Reaffirms t*hat weapons and military equipment sold or supplied in accordance with the exemption in paragraph 21 of this resolution shall not be resold to, transferred to, or made available for use by any individual or entity not in the service of the Somali National Security Forces or Somali security sector institution to which it was originally sold or supplied, or the selling or supplying State or international, regional or subregional organisation;

Approvals and notifications required under the arms embargo

23. *Reaffirms* that deliveries of items in Annex A to this resolution, intended solely for the development of SNSF, to provide security for the Somali people, require an advance approval by the Committee on a case-by-case basis, requests for which shall be submitted at least five working days in advance by the FGS or the State or international, regional or subregional organisation delivering assistance;

24. *Reaffirms* that deliveries of items in Annex B to this resolution, intended solely for the development of SNSF, to provide security for the Somali people, are subject to notifications to the Committee for information submitted at least five working days in advance by the FGS or the State or international, regional or subregional organisation delivering assistance;

25. *Reaffirms* that deliveries of items in Annex A to this resolution, intended solely for the development of SSSIs, to provide security for the Somali people, require an advance approval by the Committee on a case-by-case basis, requests for which shall be submitted at least five working days in advance by the supplying State or international, regional or sub-regional organisation and *requests* States or international, regional and sub-regional organisations to inform the FGS in parallel of any such deliveries at least five working days in advance;

26. *Reaffirms* that deliveries of items in Annex B to this resolution or the delivery of technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities, intended solely for the development of SSSIs, to provide security for the Somali people, may be provided in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of receiving a notification from the supplying State or international, regional and sub-regional organisation, and *requests* States or international, regional and sub-regional organisations to inform the FGS in parallel of any such deliveries at least five working days in advance;

27. *Reaffirms* that the delivery of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use shall be notified to the Committee five days in advance for its information only, by the supplying State or international, regional or subregional organisation;

Further information on approvals and notifications

28. *Reaffirms* that the FGS has the primary responsibility to seek approval from or notify the Committee pursuant to paragraph 23 or 24, as applicable, of any deliveries of weapons and military equipment to the SNSF, at least five days in advance, and that all requests for approvals and notifications should include: details of the manufacturer and supplier of the weapons and military equipment, a description of the arms and ammunition including the type, calibre and ammunition, proposed date and place of delivery, and all relevant information concerning the intended destination unit in the SNSF, or the intended place of storage;

29. *Reaffirms* that the State or international, regional or subregional organisation delivering weapons and military equipment to the SNSF pursuant to paragraph 23 or 24, may alternatively, make an advance request for approval or notification, as applicable, in consultation with the FGS, *reaffirms* that a State or international, regional or subregional organisation choosing to do so should inform the appropriate national coordinating body within the FGS of the advance request for approval or notification and provide the FGS with technical support with notification procedures where appropriate, and requests the Committee to transmit advance requests for approval and notifications from States or international, regional or subregional organisations to the appropriate national coordinating body in the FGS;

30. *Reaffirms* that a State or international, regional or subregional organization delivering any weapon and military equipment, technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities to SSSIs, pursuant to paragraph 25 or 26, has responsibility for seeking approval from or notifying the Committee, as applicable, for any deliveries of those items, advice, assistance or training, and informing the FGS in parallel at least five working days in advance and *decides* that all requests for approvals and notifications should include: details of the manufacturer and supplier of the weapons and military equipment including serial numbers, a description of the arms and ammunition including the type, calibre and ammunition, proposed date and place of delivery, and all relevant information concerning the intended destination unit, or the intended place of storage;

31. *Notes with concern* reports that States were not adequately following the notification procedures set out in prior resolutions, *reminds* States of their obligations pursuant to the notification procedures, set out in paragraphs 23–30 above, and *further urges* States to follow strictly the notification procedures for providing assistance to SSSIs including informing the FGS;

32. *Reaffirms* that where paragraphs 23 or 24 apply the FGS shall no later than 30 days after the delivery of weapons and military equipment, submit to the Committee a post-delivery notification in the form of written confirmation of the completion of any delivery to the SNSF, including the serial numbers for the weapons and military equipment delivered, shipping information, bill of lading, cargo manifests or packing lists, and the specific place of storage, and recognises the value of the supplying State or international, regional or subregional organisation doing the same, in cooperation with the FGS;

33. *Decides* that where paragraphs 25 or 26 apply the supplying State or international, regional or sub-regional organisation shall, no later than 30 days after the delivery of weapons and military equipment, submit to the Committee a post-delivery notification in the form of written confirmation of the completion of any delivery to the SSSI, including the serial numbers for the weapons and military equipment delivered, shipping information, bill of lading, cargo manifests or packing lists and the specific place of storage, and inform the FGS in parallel;
Further exemptions to the arms embargo

34. *Reaffirms* that the arms embargo shall not apply to:

(a) Supplies of weapons or military equipment or the provision of technical advice, financial and other assistance, and training related to military activities intended solely for the support of or use by United Nations personnel, including the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM), the African Union Mission in Somalia (AMISOM); AMISOM's strategic partners, operating solely under the latest African Union Strategic Concept of Operations, and in cooperation and coordination with AMISOM; and the European Union Training Mission (EUTM) in Somalia, all as per paragraph 10 (a)–(d) of resolution 2111 (2013);

(b) Supplies of weapons and military equipment destined for the sole use of States or international, regional and subregional organisations undertaking measures to suppress acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, upon the request of the FGS and for which the FGS has notified the Secretary -General, and provided that any measures undertaken shall be consistent with applicable international humanitarian and international human rights law;

(c) Supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Somalia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only;

(d) Entry into Somali ports for temporary visits of vessels carrying weapons and military equipment for defensive purposes provided that such items remain at all times aboard such vessels (as previously affirmed by paragraph 3 of resolution 2244 (2015));

Part 3: Targeted Measures

35. *Recalls* its decisions in its resolution 1844 (2008) which imposed targeted sanctions and its resolutions 2002 (2011), and 2093 (2013) which expanded the listing criteria, and recalls its decisions in its resolutions 2060 (2012) and 2444 (2018), and *further recalls* that the listing criteria includes, but is not limited to, planning, directing or committing acts involving sexual and gender-based violence, and *reiterates* its request for Member States to assist the Panel of Experts in its investigations, and for the FGS, FMS and AMISOM and partners to share information with the Panel of Experts regarding conduct or activities, in particular Al –Shabaab activities, where covered by listing criteria;

36. *Requests* the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and the Special Representative for Sexual Violence in Conflict to share relevant information with the Committee in accordance with paragraph 7 of resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011), and *invites* the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to share relevant information with the Committee, as appropriate;

37. *Reaffirms* that without prejudice to humanitarian assistance programmes conducted elsewhere, the measures imposed by paragraph 3 of its resolution 1844 (2008) shall not apply to the payment of funds, other financial assets or economic resources necessary to ensure the timely delivery of urgently needed humanitarian assistance in Somalia, by the United Nations, its specialised agencies or programmes, humanitarian organisations having observer status with the United Nations General Assembly that provide humanitarian assistance, and their implementing partners including bilaterally or multilaterally funded non -governmental organisations participating in the United Nations Humanitarian Response Plan for Somalia;

Panel of Experts on Somalia

38. *Decides* to renew, with effect from the date of adoption of this resolution, until 15 December 2022, the Panel on Somalia and that the mandate of the Panel shall include the tasks referred to in paragraph 11 of resolution 2444 (2018) and paragraph 2 of this resolution, *requests* the Secretary-General to include dedicated gender expertise, in line with paragraph 11 of its resolution 2467 (2019) and further requests the Panel to include gender as a cross-cutting issue in its investigations and reporting, and expresses its intention to review the mandate of the Panel and take appropriate action regarding any extension to the mandate no later than 15 November 2022;

39. *Recalls* the importance of full co-operation between the FGS and the Panel, *requests* the FGS to facilitate for the Panel interviews of suspected members of Al-Shabaab and ISIL held in custody, *notes* the importance of the Panel carrying out their mandate in line with document S/2006/997, and *requests* the Panel to give recommendations to the Committee on how to support the FGS in weapons and ammunition management, including efforts towards establishing a National Small Arms and Light Weapons Commission;

40. *Reiterates* its request for States, the FGS, the FMS and AMISOM to provide information to the Panel, and assist them in their investigations, *urges* the FGS and the FMS to facilitate access for the Panel, on the basis of written requests to the FGS by the Panel, to all FGS armouries in Mogadishu, all FGS -imported weapons and ammunition prior to distribution, all FGS military storage facilities in Somalia National Army (SNA) sectors and all captured weaponry in FGS and FMS custody, and to allow photographs of weapons and ammunition in FGS and FMS custody and access to all FGS and FMS logbooks and distribution records, in order to enable the Security Council to monitor and assess implementation of this resolution;

Reporting

41. *Requests* the Panel to provide regular updates to the Committee, including a minimum of four different thematic reports delivered on a quarterly basis, including one of smuggling and trafficking on weapons and military equipment, a comprehensive mid-term update and, for the Security Council's consideration, through the Committee, a final report by 15 October 2022 and *urges* the Panel to seek feedback from the Committee on the findings of their reporting;

42. *Requests* the Secretary-General to provide to the Council, no later than 15 September 2022, and following completion of a technical assessment of Somalia's weapons and ammunition management capability, recommendations to improve it further and to articulate options for clear, well identified, and realistic benchmarks that could serve in guiding the Security Council in its review of the arms embargo measures in light of progress achieved to date and compliance with this resolution, and particularly its consideration of possible modification, suspension or lifting of those measures;

43. *Requests* the Emergency Relief Coordinator to report to the Security Council by 15 October 2022 on the delivery of humanitarian assistance in Somalia and on any impediments to the delivery of humanitarian assistance in Somalia;

44. *Requests* the FGS to report to the Security Council in accordance with paragraph 9 of resolution 2182 (2014) and as requested in paragraph 7 of resolution 2244 (2015), by 1 February 2022 and then by 1 August 2022, including:

(a) the structure, composition, strength and disposition of its security forces, and the status of regional and militia forces,

(i) including as annexes the reports of the Joint Verification Team (JVT) requested in paragraph 7 of resolution 2182 (2014) and para 37 of resolution 2551 (2020), and

(ii) incorporating the notifications regarding the destination unit in the SNSF or the place of storage of military equipment upon distribution of imported arms and ammunition;

(b) an update summarising suspicious activity documented by domestic financial institutions, and investigations and actions undertaken by the Financial Reporting Centre to counter the financing of terrorism and in a manner so as to

protect the confidentiality of sensitive information;

(c) an update on the status of individuals designated by the Committee, where information is available;

45. *Requests* the Secretary-General to provide the Security Council with an update, no later than the 31 July 2022 on any further developments towards the normalisation of relations between Eritrea and Djibouti;

46. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex A

Items subject to the Committee's advance approval

1. Surface to air missiles, including Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS);

2. Weapons with a calibre greater than 12.7 mm, and components specially designed for these, and associated ammunition;

Note: (This does not include shoulder fired anti-tank rocket launchers such as RPGs or LAWs (light anti-tank weapon), rifle grenades, or grenade launchers.);

3. Mortars with a calibre greater than 82 mm and associated ammunition;

4. Anti-tank guided weapons, including Anti-tank Guided Missiles (ATGMs) and ammunition and components specially designed for these items;

5. Charges and devices specifically designed or modified for military use; mines and related materiel;

6. Weapon sights with a night vision capability;

7. Aircraft, specifically designed or modified for military use;

Note: "Aircraft" means fixed wing, swivel wing, rotary wing, tilt rotor or tilt wing vehicle, or helicopter.

8. "Vessels" and amphibious vehicles specifically designed or modified for military use;

Note: "Vessel" includes any ship, surface effect vehicle, vessel of small waterplane area or hydrofoil and the hull or part of the hull of a vessel.

9. Unmanned combat aerial vehicles (listed as Category IV in the UN Register of Conventional Arms).

Annex B

Equipment requiring a notification with regard to deliveries to the Somali National Security Forces and Committee approval for Somalia security sector institutions other than those of the FGS

- All types of weapons with a calibre up to 12.7mm: and associated ammunition;
- RPG-7 and recoilless rifles, and associated ammunition;
- Helmets manufactured according to military standards or specification, or comparable national standards;
- Body armour or protective garments, as follows:

◦ Soft body armour or protective garments, manufactured to military standards or specifications, or their equivalents;

Note: military standards or specifications include, as a minimum, specifications for fragmentation protection.

◦ Hard body armour plates providing ballistic protection equal to or greater that level III (NIJ 0101.06 July 2008) or national equivalents;

- Ground vehicles specifically designed or modified for military use;
- Communication equipment specifically designed or modified for military use
- Global Navigation Satellite Systems (GNSS) positioning equipment, specifically designed or modified for military use.

Annex C

Improvised Explosive Devices (IED) Components

Explosive materials, explosives precursors, explosive-related equipment, and related technology

Part I

1. Explosive materials, as follows, and mixtures containing one or more thereof:

a. Nitrocellulose (containing more than 12.5% nitrogen w/w);
b. Trinitrophenylmethylnitramine (tetryl);
c. Nitroglycerin (except when packaged/prepared in individual medicinal doses).

2. Explosive-related goods:

a. Equipment and devices specially designed to initiate explosives by electrical or non-electrical means (e.g. firing sets, detonators, igniters, detonating chord).

3. "Technology" required for the "production" or "use" of the items listed at paras. 1 & 2

Part II

1. Explosive materials, as follows, and mixtures containing one or more thereof:

a. Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO);
b. Nitroglycol;
c. Pentaerythritol tetranitrate (PETN);
d. Picryl chloride;
e. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT).

2. Explosives precursors:

a. Ammonium nitrate;
b. Potassium nitrate;
c. Sodium chlorate;
d. Nitric acid;
e. Sulphuric acid.

Annexure 7

Resolution 2628 (2022)

Adopted by the Security Council at its 9009 meeting, on 31 March 2022

The Security Council,

Recalling all its previous resolutions and statements of its President on the situation in Somalia, and reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence, and unity of Somalia,

Recalling that the Federal Government of Somalia (FGS) has primary responsibility for ensuring security in Somalia, and *recognising* Somalia's request for continued international support to enable it to achieve progressively its aim of a secure, stable, peaceful, united and democratic country,

Stressing that international support should be provided in-line with the strategic direction set out by Somalia in the Somalia Transition Plan (STP), and National Security Architecture (NSA) and *urging* enhanced partnership and coordination between all stakeholders in support of stabilisation and state-building processes in Somalia,

Commending the contribution of the African Union Mission in Somalia (AMISOM) to building lasting peace and stability in Somalia since it was first authorised 15 years ago, and *paying tribute* to all AMISOM personnel, and Somali forces, especially those who gave their lives to their mission,

Welcoming the support provided by the United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) to AMISOM, *appreciating* the financial support provided to AMISOM by the European Union and other donors, and *noting* the bilateral support provided by Member States to Somalia,

Recognising that the security situation in Somalia has changed significantly since AMISOM was first authorised, and noting improvements in Somalia's capacity and capability to respond to security challenges,

Reaffirming the need to combat terrorist threats by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and other obligations under international law, including applicable international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law, and *reaffirming* that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivations, whenever, wherever and by whomsoever committed,

Expressing grave concern that Al-Shabaab continues to pose a serious threat to the peace, security and stability of Somalia and the region, and noting its increased use of improvised explosive devices (IEDs) and exploitation of the licit financial system,

Expressing grave concern at the continued presence in Somalia of affiliates linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL also known as Da'esh),

Recognising that the nature of the threat posed by Al-Shabaab has evolved, and that international support to Somalia must adapt accordingly to consolidate the security gains achieved to date and ensure continued progress towards a more stable, secure and peaceful Somalia,

Recalling the need for a reconfigured African Union mission in Somalia, which is focussed on enabling and supporting Somalia to take primary responsibility for its security, and *expressing appreciation* for Somalia and the African Union's joint effort to update AMISOM's Concept of Operations (CONOPS) in line with the STP and in close cooperation with the United Nations and international partners, to help inform decisions about the size and shape of the future mission, including its logistical requirements,

Noting with appreciation the proposal submitted to the Security Council on 7 March 2022 by the Secretary-General, and produced jointly with the African Union, in consultation with the FGS and donors, for the strategic objectives, size and composition of a reconfigured African Union mission in Somalia, as requested in resolution 2568 (2021) (hereafter Joint Proposal),

Noting the African Union Peace and Security Council's communique of its 1068th meeting on 8 March 2022, and its decision to reconfigure AMISOM into the African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS),

Stressing the need to ensure robust command and control and operational coordination, both among African Union deployed troop and police contingents and in the force generation and integration efforts of Somalia,

Emphasising the importance of capacity building and security sector reform to enable integrated Somali security forces and institutions to respond effectively to security threats, and *further emphasising* the importance of coordination between the FGS, Somalia's Federal Member States (FMS), United Nations, African Union, and Somalia's international partners, to ensure capacity building and security reform is joined-up, and enables Somalia to assume full responsibility for its security,

Recognising that military action alone will not be sufficient to resolve threats to peace and security in Somalia, *emphasising* that the protection of civilians is critical to build sustainable peace, and reiterating the need to pursue a holistic approach that reinforces the foundations of peace and stability, in line with priorities defined by Somalia including through enhancing:

(i) effective governance and public administration,

(ii) anti-corruption,
(iii) preventing organised crime,
(iv) the rule of law,
(v) justice and law enforcement,
(vi) efforts to counter terrorism,
(vii) efforts to promote terrorist disengagement and defections,
(viii) preventing and countering violent extremism conducive to terrorism,
(ix) security sector reform, and
(x) inclusive politics and reconciliation,

Noting the potential of international cooperation and support for peacebuilding and post-conflict reconstruction and development in Somalia, if provided in line with priorities defined by the Somali authorities, and *further noting* in this regard the African Union Post-Conflict Reconstruction and Development (AUPCRD) policy and the AUPCRD dedicated centre in Cairo,

Underlining the critical importance of the FGS and FMS reaching inclusive political agreements, urging them to collaborate on security and other national priorities, *noting* the responsibilities of all parties to improve cooperation and engage in discussions for the benefit of all Somalis, and underscoring that full cooperation of all parties would advance progress on national priorities including:

(i) implementation of the National Security Architecture,

(ii) implementation of the STP,

(iii) ensuring a fully functioning federal system, and

(iv) finalising the constitution as the legal and political foundation for Somalia's government and institutions,

Welcoming the support provided by the United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) in this regard, and *recalling* its request in resolution 2592 (2021) for a strategic review of UNSOM after the completion of the current electoral process,

Noting that UNSOM and ATMIS have complementary mandates to support peace and reconciliation in Somalia, and that by providing security and strengthening Somalia's security capacity, ATMIS will make a critical contribution to justice, local governance, peace and reconciliation,

Recognising the complementary work of the United Nations Panel of Experts for Somalia and the role of sanctions imposed by the United Nations Security Council, as, among other things, a non-military means of reducing the destabilising impact of Al-Shabaab's activities in Somalia and the region, and supporting Somalia with security sector reforms, especially weapons and ammunition management,

Recalling its resolution 1325 (2000) and subsequent resolutions, *recognising* the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peacebuilding, and stressing the importance of the full, equal and meaningful participation and involvement of women in all efforts at all levels for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase the role of women in decision-making and leadership regarding conflict prevention and resolution, as envisaged in the Somali Women's Charter,

Condemning violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law in Somalia, *calling* on all parties to act in full compliance with their obligations under international human rights law and international humanitarian law,

Expressing serious concern about the humanitarian situation in Somalia, and calling for all parties to the conflict to allow and facilitate, in accordance with relevant provisions of international law, including applicable international humanitarian law, and in a manner consistent with the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance (United Nations General Assembly resolution 46/182), including humanity, neutrality, impartiality and independence, the provision of humanitarian assistance necessary to support Somalia

Emphasising the need for adequate risk assessment and risk management strategies by the FGS and the United Nations, of climate change, other ecological changes, natural disasters and other factors on the stability of Somalia,

Determining that the situation in Somalia continues to constitute a threat to regional and international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

Somalia

1. *Welcomes* the 27 September 2020, 27 May 2021 and 09 January 2022 agreements, and *urges* the FGS and FMS to ensure any disputes over implementation of these agreements are resolved peaceably so the electoral process can be completed without further delay, and *underscores* that completing the electoral process, and achieving a peaceful transition of power, will help to progress national priorities and support transition from international security support in line with the STP and NSA;

2. *Underscores* the importance of progress on national priorities, including: the NSA, STP, the ninth National Development Plan, reaching agreement on a federated police and justice system, fiscal federalism, power and resource -sharing, the constitutional review, and local and national reconciliation, and in this regard welcomes the roadmap agreed on 27 May 2021, and urges Somalia to implement it without delay;

3. *Reaffirms* the importance of the full, equal, meaningful and effective participation of women, and the inclusion of all Somalis, including, youth, persons with disabilities, Internally Displaced Persons (IDPs) and refugees in the prevention and resolution of conflicts, reconciliation processes, peacebuilding and elections and other political processes, and *acknowledges* the contribution that civil society can make in this regard and *calls on* Somalia to provide a safe environment for civil society organisations to work freely and protect them from threats and reprisals;

4. *Reiterates* its objective of enabling Somalia to take full responsibility for its own security, including through assuming the leading role in countering and addressing the threat posed by Al-Shabaab, including through the conduct of military operations to degrade Al-Shabaab's capabilities, and *strongly urges* Somalia to use the opportunity and support provided by the international community to prioritise the implementation of the STP and NSA and the generation of accountable, affordable and able security forces so that ATMIS can continue its phased drawdown, and Somalia can assume full responsibility for its own security;

5. *Calls on* the Somali authorities to ensure the delivery of the STP and NSA is properly resourced, including the command, control and coordination mechanisms required to enable the planning, conduct and delivery of joint operations with ATMIS as well as the development of necessary logistical support capabilities;

6. *Underscores* the primary responsibility for protecting civilians of the Somali authorities, and *further underscores* the importance of protecting civilians in accordance with relevant provisions of international human rights law and international humanitarian law;

7. *Calls on* the Somali authorities, with the coordinated support of the international community, to assume progressively greater responsibility for national security, and to develop and implement a strategic plan to generate new security forces, integrate existing forces where appropriate, and train and equip current and newly generated forces, with clear targets and timelines and, in this regard, *welcomes* the FGS' intention to generate a further

(a) 3850 security forces by December 2022;
(b) 8525 security forces by September 2023;
(c) 10450 security forces by June 2024;

8. *Calls on* the FGS to work with the FMS on the process for force generation and integration of regional forces, noting the need for enhanced capacity and capabilities, within timelines that are compatible with the Joint Proposal and CONOPs;

9. *Calls on* the Somali authorities to enhance civilian oversight and accountability of their security apparatus and to continue to adopt and implement appropriate vetting procedures of all defence and security personnel, including human rights vetting;

10. *Reaffirms* the essential role of the police and justice sector in stabilization efforts and the preparation and conduct of elections, *calls on* Somalia to fully support the state and federal police through effective training, provision of equipment, and sustainment support, *reiterates* the critical role police play in securing and holding territory and *emphasises* that a professional and capable police force, able to contribute to providing security for civilian populations, is necessary for Somalia to fully implement the STP and NSA, and *encourages* inclusive and representative Somali security and police force recruitment from all sections of Somali society;

11. *Calls on* Somalia to ensure all security and police forces fully respect international human rights law and international humanitarian law and to ensure that those responsible for violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law are held accountable, *further calls on* the United Nations, African Union and other international partners to support the Somali authorities with this as appropriate and *requests* that ATMIS share the experience and lessons-learnt from the operation of the Civilian Casualty Tracking Analysis and Response Cell (CCTARC) with national authorities, including with a view to supporting the development of Somali civilian casualty monitoring, mitigation, and prevention policies and mechanisms;

12. *Calls on* the Somali authorities, in coordination with ATMIS, international partners, and relevant United Nations entities, including UNMAS, to combat the illicit trade, transfer, diversion and accumulation of small arms and light weapons, to prevent access of unauthorised recipients to all types of explosives and related materials in Somalia, and to ensure their safe and effective management and storage;

13. *Underlines* the need for Somalia and its international partners to consider the security situation in each location during transition of security responsibilities from ATMIS to Somalia, and *emphasises* that planning, and decision-making should be guided by a comprehensive assessment of the threat to civilians, and that proactive measures to mitigate risks should be taken, including by establishing an appropriately sized, qualified and accountable Somali security and police force presence to ensure continued security and protection before, during and after military action;

14. *Recalls* resolutions 1612 (2005) and subsequent resolutions on Children and Armed Conflict and *expresses its grave concern* over reports of killing, maiming, rape and other forms of sexual violence used against children in armed conflict as well as unlawful recruitment and use, re-recruitment, including in non-combatant roles, and the abduction of children, and calls on the Somali authorities to:

(a) strengthen the legal framework on child protection and underscores the need for capacity building on child protection;

(b) take action to prevent all forms of violence against children and to hold those responsible to account;

(c) take appropriate measures to prevent attacks against civilian infrastructure including against schools and hospitals, and to prevent their military use;

(d) cease detentions of all children on national security charges where this is in violation of applicable international law and instead to treat children primarily as victims, consistent with Somalia's obligations under the United Nations Convention on the Rights of the Child; and

(e) take action to fully implement their 2012 Action Plans, the 2014 standard operating procedures for the handover of children separated from armed groups, the 2018 Roadmap and the Working Group Conclusions on Children and Armed Conflict in Somalia (S/AC.51/2020/6);

15. *Calls on* all parties to armed conflict in Somalia to end sexual and gender- based violence and further calls on Somali authorities to work with relevant partners to:

(a) ensure protection for all from sexual and gender-based violence, and conflict-related sexual violence;

(b) ensure a survivor-centred and gender- and age-sensitive approach to preventing and responding to sexual and gender-based violence;

(c) take appropriate steps to investigate alleged abuses and prosecute alleged perpetrators to stop impunity;

(d) strengthen legislation to support accountability in line with resolution 2467 (2019) and other relevant resolutions; and

(e) accelerate the implementation of the Joint Communiqué and the National Action Plan on prevention of, and response to sexual violence in conflict;

16. *Strongly* condemns attacks as well as threats of attacks that are in contravention of international humanitarian law against schools and civilians connected with schools and *urges* all parties to armed conflict to immediately cease such attacks and threats of attacks and to refrain from actions that impede access to education;

17. *Recalls* its resolution 2417 (2018) and expresses grave concern at the ongoing humanitarian crisis in Somalia and its impact on the people of Somalia, encourages all partners including donors to maintain humanitarian assistance in 2022, *strongly condemns* any indiscriminate or direct attacks against humanitarian and medical personnel and civilian infrastructure, including by Al-Shabaab, as well as any misuse or obstruction of humanitarian assistance, *reiterates* its

demand that all parties allow, in accordance with relevant provisions of international law and in line with humanitarian principles, full, safe, rapid and unhindered access for the timely delivery of humanitarian assistance to persons in need across Somalia, and *underlines* the importance of proper accounting of international humanitarian support;

Al-Shabaab and affiliates linked to ISIL

18. *Condemns* in the strongest terms the attacks by Al-Shabaab targeting security forces, and its terrorist attacks against government officials, civilians, and civilian infrastructure in Somalia and the wider region, as well as incidents of hostage-taking and kidnapping of civilians, its recruitment, training and use of foreign terrorist fighters, and *notes with concern* that these activities constitute a threat to peace and security in Somalia, regional stability, integration and development, and exacerbate humanitarian suffering;

19. *Reiterates* that the FGS has the primary responsibility for ensuring security in Somalia, and *calls* on Somalia to prioritise, coordinate and strengthen efforts to counter Al-Shabaab and affiliates linked to ISIL in a comprehensive manner, including through but not limited to the use of military operations to deg rade their capabilities and disrupt their ability to access financial resources, weapons and ammunition, in full compliance with its obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law as applicable;

20. *Reaffirms* that all States shall prevent and suppress terrorist acts, urges all States to take action against Al-Shabaab and affiliates linked to ISIL in Somalia, in accordance with conventions dealing with terrorism, as well as applicable United Nations Security Council resolutions, including resolution 1373 (2001) and further reaffirms that Member States must ensure that any measures taken to counterterrorism comply with the Charter of the United Nations and all other obligations under international law, including international humanitarian law, international human rights law, and international refugee law;

21. *Requests* Somalia to strengthen cooperation and coordination with other Member States, particularly other Member States in the region, to prevent and counter the financing of terrorism, including compliance with resolution 1373 (2001), resolution 2178 (2014), resolution 2462 (2019), and urges Somalia, with the support of the African Union, the United Nations and other Member States to work closer together to increase the delivery of non-military activities to degrade Al-Shabaab and affiliates linked to ISIL, to prevent them conducting activities that harm the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia, to counter their terrorist activities, illicit finance, organised crime, access to, and trafficking in, arms and ammunition, including small arms and light weapons, IED manufacture, justice and propaganda activities, and to work, together with the international community, to implement the measures set out in 2607 (2021), including those measures imposed against individuals and groups designated by the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992);

ATMIS

22. *Endorses* the African Union Peace and Security Council's decision to reconfigure AMISOM into the African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS), and *authorises*, for an initial period of 12 months, the Member States of the African Union to take all necessary measures, in full compliance with participating States' obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, and in full respect of the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia, to:

(a) carry out its mandate to reduce the threat posed by Al-Shabaab;

(b) support the capacity building of the integrated Somali security and police forces;

(c) conduct a phased handover of security responsibilities to Somalia; and

(d) to support peace and reconciliation efforts in Somalia, in line with the STP and NSA, in support of the development of a stable, federal, sovereign and united Somalia;

23. *Decides* to authorise ATMIS to pursue the following strategic objectives as outlined in the Joint Proposal:

(a) conducting jointly planned and targeted operations with Somali security forces to degrade Al-Shabaab and affiliates linked to ISIL;

(b) support Somali security forces by jointly holding priority population centres and providing protection for the local communities, United Nations personnel and installations, securing main supply routes identified by the FGS, and coordinating with stabilisation and reconciliation actors in collaboration with Somali security forces, to support the implementation of the Somali National Stabilisation Strategy and State Stabilisation Plans;

(c) assisting the FGS in the implementation of stabilisation efforts for all recovered areas in coordination with Community Recovery and Extension of State Authority and Accountability (CRESTA/A) and other stabilisation actors;

(d) supporting the capacity development of the Somali security forces with priority given to force generation, operational competencies and logistical support capabilities to facilitate progressive takeover of security responsibilities in Somalia;

(e) supporting Somali security forces across the clear, hold and build phases, in line with the STP, and in collaboration with federal government institutions by facilitating humanitarian liaison, community engagement as well as assisting Somali security forces with complying with international humanitarian law and international human rights law and holding accountable those responsible for violations thereof;

24. *Decides* to authorise ATMIS' military, police and civilian components to conduct the tasks outlined in paragraphs 33 to 39 of the Joint Proposal, and recalls the CONOPs provides the following tasks:

(a) conduct joint simultaneous targeted offensive operations across all sectors, in coordination with Somali security forces to degrade Al -Shabaab and affiliates linked to ISIL;

(b) support Somali security forces in providing security for the political process at all levels, including stabilisation efforts, reconciliation and peacebuilding;

(c) configure ATMIS in terms of composition, structure, disposition and equipment, to best support the handover of security responsibility to Somali security forces;

(d) support Somali security forces in clearing main supply routes, including to areas recovered from Al-Shabaab; provide combat mentorship to the Somali National Army; enhance Somali National Army capacity to conduct civil-military coordination activities;

(e) jointly with partners, enhance Somali National Army capacity to conduct counter improvised explosive devices operations;

(f) ensure compliance with the rules of engagement, international humanitarian law, international human rights law and all international best practices;

(g) support specialized training, advising and mentoring and provide operational support, including joint patrols and protection of vital installations, to the Somali police in line with the Somali Transition Plan;

(h) support the service delivery capacity of the Somali police in the provision of policing services, across Somalia through police generation and deployments;

(i) support police-public partnerships for increased resilience to radicalisation to violence, violent extremism conducive to terrorism and social disorder through community policing and to support the efforts of the Somali police forces in the compliance of international humanitarian law, international human rights law, women peace and security resolutions and conduct and discipline standards;

(j) across the clear-hold-build phases of ATMIS operations, undertake activities to support the ATMIS uniformed components, as well as Somali security forces operating jointly with ATMIS, to carry out their operations in full compliance with obligations under international humanitarian law, international human rights law, and in compliance with the Human Rights Due Diligence Policy on United Nations support to Non-United Nations security forces (HRDDP), as well as in compliance with the African Union Compliance and Accountability Framework for Peace Support Operations;

(k) support early recovery initiatives in newly recovered areas, and humanitarian liaison;

(l) support the implementation of the Somali National Stabilisation Strategy;

(m) support relevant Somali ministries and institutions to implement the Somali Transition Plan priorities and provide necessary support in realising the objectives of ATMIS;

25. *Affirms* that where resolution 2607 (2021) refers to "AMISOM", it shall be read as referring to ATMIS;

26. *Authorises* the Member States of the African Union to deploy up to 19,626 uniformed personnel, inclusive of a minimum of 1040 police personnel including five Formed Police Units, until 31 December 2022 and *endorses* the African Union Peace and Security Council's decision to drawdown 2000 personnel by this date;

27. *Authorises* the Member States of the African Union, between 1 January 2023 and 31 March 2023, to deploy up to 17,626 uniformed personnel, inclusive of a minimum of 1040 police personnel including five Formed Police Units;

28. *Notes* the Joint Proposal and CONOPs envisage further reductions to 14,626 uniformed personnel, inclusive of a minimum number of 1040 police by the end of phase 2 (September 2023), 10,626 uniformed personnel, inclusive of a minimum number of 1040 police personnel by the end of phase 3 (June 2024), and zero personnel, by the end of phase 4 (December 2024), and *expresses its intention* to authorise, taking into account the situation in Somalia and the regular, joint technical assessments outlined in paragraph 51 to this resolution, these reductions;

29. *Requests* the African Union to ensure structures are in place to provide:

(a) clear oversight of ATMIS, and accountability mechanisms for the mission and its contingents;

(b) clear command and control of the mission and operational coordination between its contingents;

(c) coordinated operational decision making under the Force Commander and Sector Commanders;

(d) command, control and accountability of mission enabling units, including air assets;

(e) the creation, and deployment of mobile forces in ATMIS sectors; and

(f) that ATMIS instructions are to remain politically neutral and prioritise the protection of civilians;

30. *Urges* the African Union, with United Nations support, taking into consideration Statement of Unit Requirements (SURs), and within existing resources, to continuously review ATMIS' operational capabilities to:

(a) enhance force protection to carry out mandated tasks; and
(b) identify gaps in resource requirements, and produce specific requests for resources and

equipment to be fulfilled through voluntary contributions;

31. *Underlines* the importance of ATMIS forces continuing to cooperate with UNSOM and UNSOS in implementing the HRDDP across the preparatory, conduct and review phases of operations, including in the context of joint or coordinated operations with Somali security and police forces, and *recognises* the role that the African Union Compliance Framework and its operationalisation in ATMIS can play in enhancing compliance with international human rights law and international humanitarian law;

32. *Calls on* ATMIS to undertake, and on the African Union to ensure, regular monitoring and prompt and thorough investigations into and reporting on allegations of human rights violations and abuses and violations of international humanitarian law by ATMIS forces, as well as ensuring the highest standards of transparency, and conduct and discipline, and, where appropriate, harmonisation of their procedures with UNSOM, and *urges* troop- and police-contributing countries to strengthen their cooperation with the African Union and the United Nations to ensure the effectiveness of the ATMIS compliance and accountability measures;

33. *Requests* ATMIS to work closely with the CCTARC across all sectors, and underlines the importance of ensuring information is shared with relevant actors including the United Nations, is integrated into ATMIS reporting, and feeds into operational guidelines and plans, and *requests* the full support of troop and police contributors to the CCTARC, in collaboration with humanitarian, human rights and protection actors;

34. *Requests* ATMIS to support the implementation of the Joint Communique and National Action Plan to prevent and respond to sexual violence in conflict, and to take into account these specific concerns throughout the activities of all ATMIS components, and to ensure that risks of sexual violence in conflict are included in data collection, threat analysis and early warning systems, *reaffirms* the importance of a zero-tolerance policy on Sexual Exploitation and Abuse, stresses the need to prevent such exploitation and abuse, *requests* the African Union and troop- and police-contributing countries to screen personnel, undertake risk assessments, deliver all relevant training to personnel, to protect and support the relief and recovery of survivors who report abuse, carry out timely investigations into allegations, to hold perpetrators accountable, and to repatriate units where there is credible evidence of widespread or systemic sexual exploitation or abuse by members of those units, and *further requests* the African Union to work closely with the United Nations in this regard;

35. *Encourages* efforts to ensure female uniformed personnel are deployed to ATMIS by the troop- and police-contributing countries, and *urges* ATMIS to ensure the full, effective and meaningful participation of women across its operations and to integrate a gender perspective throughout the delivery of its mandate;

36. *Notes* Somalia's request to the African Union on the recruitment of Somali nationals to ATMIS civilian staff positions;

UN Support Office in Somalia (UNSOS)

37. *Requests* the Secretary-General to continue to provide a logistical support package, and, in consultation with the African Union and FGS, develop an appropriate logistical support plan, in full compliance with HRDDP, through UNSOS for UNSOM, ATMIS uniformed personnel in line with paragraphs 26 and 27 to this resolution, and on the basis set out in paragraph 2 of resolution 2245 (2015), 70 ATMIS civilians, increasing to 85 ATMIS civilians from 1 January 2023, to support ATMIS' military and police tasks and enhance coordination between the United Nations, African Union and FGS, and, through the United Nations Trust Fund in Somalia, support up to 13,900 Somali security forces, including an appropriate share of the state and federal police who are formally integrated into the Somali security forces in line with the National Security Architecture and who are actively participating in joint or coordinated operations with ATMIS that directly implement the STP;

38. *Expresses its intention* to consider increasing the number of Somali security forces eligible for support through UNSOS as set out in paragraph 37, subject to progress in force integration and generation as set out in paragraphs 7 and 8 and drawdown of ATMIS uniformed personnel as set out in paragraphs 26 and 27 of this resolution;

39. *Underscores* the importance of ATMIS and the Somali security forces working jointly with UNSOS on the delivery of logistics support, including, among other things, integrating UNSOS into planning for military operations, ensuring convoy and airfield security, protection of civilians and protecting main supply routes;

40. *Underscores* that the sustainability of peace and security support is improved by the implementation of the United Nations Department of Operational Support's Environment Strategy (Phase II), which emphasises good stewardship of resources and a positive legacy of the mission, and identifies the goal of expanded renewable energy use in missions to enhance safety and security, save costs, offer efficiencies and benefit the mission, mindful of the Secretary -General's call for field operations to shift to renewable energy by 2030 to meet UNSCAP goals;

41. *Requests* the Secretary-General to continue United Nations support to Somali security forces with training, equipment and mentorship to counter the threat of improvised explosive devices (IEDs);

42. *Underscores* that oversight and accountability, in particular compliance with HRDDP, should be the cornerstone of the partnership between the United Nations, the African Union, and Somalia, *requests* the Secretary-General to ensure that any support provided to non-United Nations security forces is provided in strict compliance with the HRDDP, and *requests* Somalia and African Union to agree an updated memorandum of understanding with the United Nations on the conditions of provision of United Nations support to Somalia;

43. *Requests* the Secretary-General to work closely with the African Union in supporting the implementation of this resolution, including to provide technical and expert advice on the planning, deployment and strategic management of ATMIS in line with the mandate of the United Nations office to the African Union;

International Support

44. *Welcomes* the continued financial support provided to the African Union mission in Somalia, especially from the European Union over the past 15 years, *stresses* the importance of including financial partners in ATMIS's strategic decision - making process and stresses the importance of stringent monitoring of and accountability for financial and materiel support;

45. *Urges* Member States, including new donors, to consider providing predictable, sustainable and multi-year support for ATMIS, including through the provision of additional funding to the African Union for ATMIS' civilian component to enable its support for the implementation of the STP, NSA and broader stabilization efforts, as well as for troop and police stipends, equipment and technical assistance and to support the effective functioning of the CCTARC and disbursement of amends;

46. *Urges* Member States to consider providing funding to the United Nations Trust Fund in Somalia, including funding for training, equipment and mentoring of the Somali security and police forces, including to counter the threat of IEDs, and to top the illicit proliferation of small arms and light weapons, and support for the African Union in mobilising the required resources and equipment for ATMIS, including through financial contributions to address identified gaps in resource requirements, and specific requests for resources and equipment;

47. *Urges* Member States to consider providing bilateral funding to support national and state-level institutions develop an integrated Somali security sector, including capacity building for the maritime police force in line with resolution 2246 (2015);

48. *Underlines* the need for Somalia and its partners to take a coordinated approach towards supporting Somali-led political and security reforms, to ensure consistency, maximise impact and enable sustained, progressive transition of security responsibility to Somalia and therefore:

(a) *Urges* the FGS to lead strategic coordination through regular high-level meetings of the Somali Transition Plan Strategic Steering Committee, the Security and Justice Committee and the Somalia Development and Reconstruction Facility Committee;

(b) *Urges* the FGS to agree all joint or coordinated operations, and strategic and operational decisions, including Somali security force generation with FMS, in coordination with ATMIS and the United Nations and other international partners where relevant;

(c) *Requests* the United Nations, in coordination with the FGS, African Union and European Union, to establish a technical partnership coordination function to increase coordination and collaboration between the FGS, FMS, ATMIS, UNSOM, UNSOS, the United Nations Country Team and Somalia's other multilateral, regional and bilateral partners including by:

(i) sharing information, including the creation of a sector-by-sector dashboard of Key Performance Indicators;

(ii) conducting analysis, planning and performance assessment;

(iii) coordinating bilateral provision of capacity building support, training, mentoring and donations of equipment and supplies to Somali security and police forces;

(iv) ensuring that such support and assistance is provided in line with relevant provisions of resolution 2607 (2021); and

(v) ensuring that such support and assistance is compliant with the HRDDP;

49. *Underlines* the need to enhance the predictability, sustainability and flexibility of financing for African Union-led peace support operations authorised by the Security Council and under the Security Council's authority consistent with Chapter VIII of the Charter, and encourages the Secretary-General, African Union and Member States to continue efforts to explore in earnest funding arrangements for ATMIS, bearing in mind the full range of options available to the United Nations, African Union, the European Union, and to other partners, and considering the limitations of voluntary funding, in order to establish secure future funding arrangements for ATMIS;

Evaluation and Reporting

50. *Requests* the United Nations, jointly with the African Union, FGS, European Union and other donors, to identify through an inclusive, consultative process: relevant, clear and realistic benchmarks, which include roles and responsibilities and measurable indicators for security transition, and that take into account the needs of all segments of the population, in order to assess the implementation of security transition, including benchmarks for the effectiveness of ATMIS, proposed by the African Union and benchmarks for the implementation of the STP and NSA proposed by the FGS, by 30 September 2022, taking into account resolution 2594 (2021);

51. *Requests* the United Nations, jointly with the African Union FGS, European Union and other donors, to undertake regular, joint technical assessments of progress made, and against the benchmarks requested in paragraph 50 to this resolution, to guide the Security Council as it further decides on the next steps of the phased drawdown of ATMIS and support provided by UNSOS, and to report to the Security Council by 15 February 2023;

52. *Requests* the FGS to provide an update to the Security Council, by 10 July 2022, 10 October 2022, and 10 January 2023 on:

(a) progress in implementing the STP and NSA and force generation and integration, as set out in paragraphs 7 and 8 of this resolution;

(b) progress in implementing the roadmap agreed on 27 May 2021;

53. *Requests* the African Union to keep the Security Council informed, through the Secretary-General, on the implementation of ATMIS' mandate, by 10 July 2022, 10 October 2022 and 10 January 2023 and further requests in this regard, these reports contain specific reporting on:

(a) progress on joint operations in support of the STP and NSA including the use and effectiveness of coordination mechanisms with the FGS;

(b) evaluation of ATMIS' command and control mechanisms;

(c) progress against strategic objectives outlined in paragraph 23;

(d) quantitative and qualitative assessment of progress against tasks outlined in the Joint Proposal and CONOPs;

(e) accountability measures taken to address previously identified underperformance, including command and control, and conduct and discipline;

(f) the effectiveness of measures taken to protect civilians;

(g) equipment review outcomes and use of force assets;

54. *Requests* the Secretary-General to keep the Security Council regularly informed on the implementation of this resolution, in their regular reports requested in paragraph 17 of resolution 2592 (2021) and *recalls* its request for the Secretary- General to submit to the Security Council a strategic review of UNSOM, as outlined in paragraph 18 of resolution 2592 (2021) and *expresses its intention* to provide a new date for its completion following the conclusion of the current electoral process in Somalia;

55. *Decides* to remain actively seized of the matter."

[F. No. U.II/152/01/2016]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 2220(E), dated the 28th June, 2016 and last amended *vide* Order number S.O.1797 (E), dated the 12th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.30 22:51:58 +05'30'